Rural World

AN IDEA FOR A PROSPEROUS RURAL INDIA

Volume 1, Issue 1
February 2024-April 2024
Quarterly / ₹100

Making Agriculture India's Growth Engine | कृषि क्षेत्र बनेगा इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन

गांव कनेक्शन

समृद्ध ग्रामीण भारत की सोच

ruralworld.co.in
www.ruralvoice.in
eng.ruralvoice.in

@ruralvoicein
@ruralvoicein
@ruralvoicein
@ruralvoicein

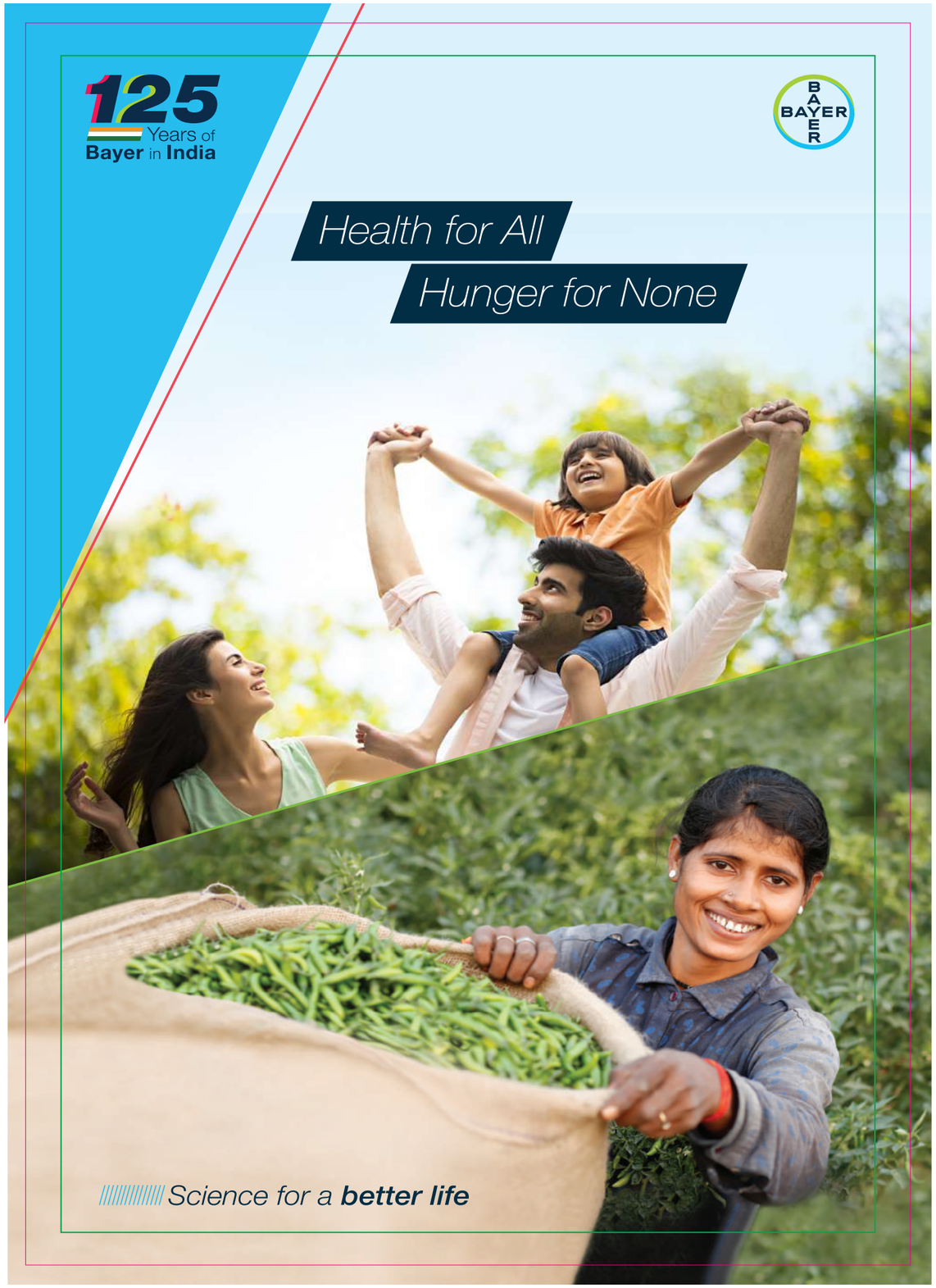

Harvir Singh
Editor-in-Chief

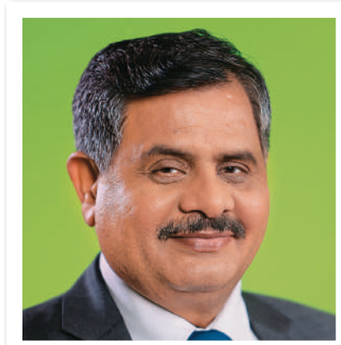

Agriculture to become growth engine of country's economy

When Rural Voice had to decide the theme of the Agriculture Conclave to be organized on its third anniversary, we realized that if the country's economy is to be strengthened, the agriculture sector will have to be kept at its center. Anyway, it is not logical to talk about strengthening the country's economy without the rapid growth of the agriculture sector, which has about 18 percent share in the country's economy and is the source of employment for 45 percent of the working people. Keeping these things in mind, our topic was decided as 'Making Agriculture Engine of Economic Growth'.

In 1991, when liberal economic policies were started through the New Industrial Policy, the belief was very strong that industrial development in the country would accelerate and a large part of the population would leave agriculture and move to industries. This will reduce the burden on agriculture and due to reduction in the number of people in rural India, the economic situation there will also improve. It is true that in the meantime urbanization and the percentage of urban population has increased in the country, but the assumption that the number of people dependent on agriculture has reduced has not proved to be correct. On the other hand, the dream of making India a manufacturing hub was also not fulfilled. The government is implementing various schemes to take manufacturing to 25 percent of the GDP, for which it also incentives worth thousands of crores of rupees every year, yet it is stuck at 12 -13 percent. According to the Labour Force Survey, after reaching about 14 percent, the share of the total number of working people included in it has now dropped to less than 12 percent.

The industrial growth rate of six per cent is increasing employment by only one per cent as the use of automation and technology in manufacturing continues to increase. In such a situation, the better option is to strengthen agriculture. NITI Aayog member Professor Ramesh Chand says that India can become a developed nation by 2047 only if the agricultural growth rate is 4.5 percent. There is a better opportunity for the government to decide its economic policies keeping agriculture at the center. This is not happening right now but it is necessary to do so. There is huge potential in the agriculture sector which can accelerate the pace of development of the country, but for that changes in the policies related to agriculture sector and better opportunities for investment are needed.

The worrying thing is that the interest of private corporates in investing in agriculture sector is very less and it is less than three percent. Most of the investment in agriculture sector is either from the public sector or the farmers themselves are investing money. This situation cannot accelerate the wheel of agricultural development. The central and state governments are giving a large part of the amount allocated for the agriculture sector in their budget in the form of income support or subsidy and the capital expenditure is negligible. In the current year's Union Budget, the capital expenditure for agriculture is less than Rs 100 crore whereas the government has made a provision of capital expenditure of Rs 11.11 lakh crore. The largest part of this is going on the development of infrastructure facilities. Not only this, government expenditure on agricultural research and education is either stable or decreasing.

The success of the Green Revolution in the country was due to public sector agricultural research institutes like ICAR and IARI and state agricultural universities. But now most of the amount allocated for them is spent on salaries only. Many of the world's largest private sector companies are spending more on research than the total budget of ICAR. There is no focus of the governments on setting up modern infrastructure facilities on the marketing front, nor is there any effective policy for value addition. The decisions of the last two years prove that the consumer, not the farmer, is at the center of the government's decisions on import and export. Such policies cannot make agriculture an engine of economic growth. The government should include all stakeholders in it, in which farmers are the most prominent. @harvirpanwar

CONTENTS

Cover Story

06 Making Agriculture India's Growth Engine

16 Hailing Bharat Ratna to Dr MS Swaminathan

18 Charan Singh wanted quota for farmers, land reform in their favour

कवर स्टोरी

42 कृषि क्षेत्र बनेगा इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन

58 टेक्नोलॉजी और इनोवेशन से गुड़-खांडसारी इंडस्ट्री का नया दौर

64 अंतरिम बजट 2024-25: 'अन्नदाता' के लिए नया कुछ नहीं

Volume 1, Issue 1
Quarter (February 2024-April 2024)

Editor
Harvir Singh

Published and Printed by Harvir Singh on behalf of Rural Voice Media Pvt. Ltd.

Printed at Multi Colour Services, Shed No. 92, DSIDC, Okhla Industrial Area Phase-1, New Delhi 110020. Published from 11-A, Skylark Apartment, DDA SFS Flats, Site-2, Ghazipur, Kalyanpuri, Delhi-110092

Editor: Harvir Singh

Published for the Quarter: February 2024-April 2024
Released on 20 February 2024

Total Number of pages 68 including covers

Website: ruralworld.co.in,
Email: contact@ruralvoice.in

COVER DESIGN
Alok Shrivastava, Socratus

DISCLAIMER: All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmited in any form, or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without the prior permission of the publisher.

हरवीर सिंह
एडिटर-इन-चीफ

कृषि ही बनेगी देश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन

रूरल वॉयस को जब अपनी तीसरी वर्षगांठ पर आयोजित होने वाले एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव का विषय तय करना था तो हमने पाया कि देश की इकोनॉमी को मजबूत करना है तो इसके केंद्र में कृषि क्षेत्र को रखना होगा। वैसे भी देश की इकोनॉमी में करीब 18 फीसदी हिस्सेदारी और 45 फीसदी कामकाजी लोगों के रोजगार का स्रोत होने के चलते कृषि क्षेत्र की तेज वृद्धि के बिना देश की इकोनॉमी को मजबूत करने की बात करना तर्कसंगत नहीं है। इन बातों को ध्यान में रखकर हमारा विषय तय हुआ 'मेकिंग एग्रीकल्चर इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ'।

साल 1991 में उदार आर्थिक नीतियों की शुरुआत न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के जरिये हुई तो यह धारणा बहुत मजबूत थी कि देश में औद्योगिक विकास तेज होगा और आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि छोड़ उद्योगों का रुख करेगा। इससे कृषि पर बोझ कम होगा और ग्रामीण भारत में लोगों की संख्या घटने से वहां आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। यह बात सही है कि इस बीच देश में शहरीकरण और शहरी आबादी का प्रतिशत बढ़ा है, लेकिन खेती पर निर्भर लोगों की संख्या कम होने की धारणा सही साबित नहीं हुई। दूसरी ओर भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का सपना भी पूरा नहीं हुआ। सरकार मैन्युफैक्चरिंग को जीडीपी के 25 फीसदी तक ले जाने के लिए तमाम योजनाएं लागू करती रही है, इसके लिए हर साल इंसेंटिव भी देती है, फिर भी यह 12 से 13 फीसदी पर अटकी है। इसमें शामिल कुल कामकाजी लोगों की संख्या की हिस्सेदारी भी करीब 14 फीसदी तक पहुंचने के बाद लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक अब 12 फीसदी से कम रह गई है।

छह फीसदी की औद्योगिक वृद्धि दर रोजगार में केवल एक फीसदी इजाफा कर रही है क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में ऑटोमेशन बढ़ रहा है। ऐसे में कृषि को मजबूत करने का विकल्प ही बेहतर है। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद का कहना है कि कृषि विकास दर 4.5 फीसदी होने पर ही 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बन सकता है। सरकार के सामने एक बेहतर मौका है कि वह कृषि को केंद्र में रखकर अपनी आर्थिक नीतियां तय करे। अभी ऐसा नहीं हो रहा है लेकिन ऐसा करना जरूरी है। कृषि क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं हैं जो देश के विकास की गति को तेज कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी नीतियों में बदलाव करना होगा और निवेश के लिए बेहतर मौके पैदा करने होंगे।

चिंताजनक बात यह है कि कृषि क्षेत्र में निवेश करने में निजी कॉरपोरेट की दिलचस्पी बहुत कम है और यह तीन फीसदी से भी कम है। कृषि क्षेत्र में अधिकांश निवेश या तो सार्वजनिक क्षेत्र का है या फिर किसान खुद पैसा लगा रहे हैं। यह स्थिति कृषि विकास के पहिये को तेज नहीं कर सकती है। केंद्र और राज्य सरकारें अपने बजट में कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित राशि का बड़ा हिस्सा इनकम सपोर्ट या सब्सिडी के रूप में दे रही हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर नगण्य है। चालू साल के केंद्रीय बजट में कृषि के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर 100 करोड़ रुपये से भी कम है जबकि सरकार ने 11.11 लाख करोड़ रुपये के कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान किया है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा ढांचागत सुविधाओं के विकास पर जा रहा है। यही नहीं, एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन पर सरकार का खर्च या तो स्थिर है या कम हो रहा है। देश को हरित क्रांति की कामयाबी सार्वजनिक क्षेत्र के कृषि शोध तंत्र आईसीएआर और आईएआरआई जैसे संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कारण मिली। लेकिन अब इनके लिए आवंटित अधिकांश राशि वेतन पर ही खर्च हो जाती है। दुनिया की निजी क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियां आईसीएआर के कुल बजट से अधिक शोध पर खर्च कर रही हैं। मार्केटिंग के मोर्चे पर आधुनिक ढांचागत सुविधाएं स्थापित करने पर सरकारों का फोकस नहीं है, न वैल्यू एडिशन की कोई कारगर नीति है। पिछले दो साल के फैसले साबित करते हैं कि आयात-निर्यात पर सरकार के फैसलों के केंद्र में उपभोक्ता है, किसान नहीं। ऐसी नीतियां कृषि को इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन नहीं बना सकती हैं। सरकार को सभी हितधारकों को साथ रखते हुए नये सिरे से सोचना होगा।

कृषि किस तरह देश की इकोनॉमी की ग्रोथ का इंजन बन सकती है, इसका क्या आधार है यह रूरल वर्ल्ड के इस अंक की कवर स्टोरी में विस्तार से बताया गया है। टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव मार्केटिंग के जरिये परंपरागत गुड़ इंडस्ट्री कैसे मॉडर्न इंडस्ट्री का रूप ले रही है, इस अंक में उस पर एक ग्राउंड रिपोर्ट है। कृषि क्षेत्र के कायाकल्प और करोड़ों किसानों के जीवन में बदलाव लाने वाले दो महान शख्सीयतों पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह और प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिक डॉ. एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। इन पर भी विशेष सामग्री है। रूरल वर्ल्ड का हर अंक देश के किसानों और कृषि क्षेत्र की बेहतरी को समर्पित है।

@harvirpanwar

Making Agriculture India's Growth Engine

To realize the dream of a developed India, it is necessary for the villages and farmers to move forward on the path of progress.

Harvir Singh • Ajeet Singh

The way to develop India's economy and take the per capita income to 12 thousand dollars will pass through farms and barns . This is not possible without a consistent annual growth rate of 4.5 percent in the agriculture sector,the largest source of employment in the country. Despite economic liberalization and unrealized intentions to raise the contribution of manufacturing in GDP, it is the agricultural sector which provides employment to 45 percent of the population. Agriculture is the backbone of the Indian economy as it is not only the largest provider of employment but also ensures the strategic food security to the country.

Going forward and on the way to realise the ambition of a developed country, a comprehensive policy and corresponding plans would be required. Ironically, such a policy does not exist at present and it is regrettable. In the year 1998, during the NDA government led by Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, a brief document showed up in the form of agricultural policy. It could be seen as a synopsis , not as a comprehensive policy. Even this stopped right at the beginning. Thereafter, policies related to agriculture were made in bits and pieces and decisions were taken on an ad hoc basis.

In the world's largest economy like America, where according to the data of 2022, there are only 20 lakh land holdings, agricultural policy is finetuned at a certain interval. The European Union also reviews its agricultural policy at regular intervals. But no one talks about this in India. This is not an issue at all; Here the maximum focus is on marketing. The focus of the aborted agricultural laws brought in June 2020, on issues related to marketing of agricultural products.

While we have to raise agriculture growth, taking advantage of the potential available in the sector , we need to frame a policy not for the farmers but also their future generations. The policy objective should be how to retain farmers making agriculture profitable; but they are moving away from agriculture landing in cities as migration becomes unchecked. Former

Director General of Indian Council of Agricultural Research (ICAR), Dr. R.S. Paroda continuously emphasizes that we have to formulate new thinking for the youth to return to agriculture and formulate and implement policies accordingly.

During the Rural Voice Agriculture Conclave organized on the third foundation day of Rural Voice last month, experts and policy makers discussed various ways to make agriculture a driver of economic development. A dialogue took place with farmer representatives. On this occasion, Dr. RS Sodhi, former MD of Amul and President of Indian Dairy Association, highlighted how the dice is always inclined in favour of consumers and not farmers in the policy makers' priorities. Rise in Bombay Sensex is seen as a symbol of progress , but when the prices of vegetables or food items increase, it is called food inflation. In fact , this thinking and attitude needs to be changed.

Dr. Sodhi says that there will be an investment of Rs 1 lakh crore in the dairy sector alone in the next 7-8 years. If the processing of milk increases by about 12 crore liters, it will create 72 lakh new employment opportunities. By the year 2023, the food market will increase more than three times to Rs 170 lakh crore. Today consumers are ready to pay higher prices for good quality and nutritious food. Therefore, farmers should shift to the food items are in demand in the marketplace. We need to make farmers to realize immense possibilities lying untapped.

Actually,land, water, energy and labour are the foundations of agriculture. Likewise, there are four technological factors to achieve better production and productivity . These are: Genetics, Crop Nutrition, Crop Protection and Agronomic Interventions. While availability of land is important , equally important is the soil health i.e. the presence of fertile elements in it and their continuous improvement. At the same time, many experts are linking the increasing trend of contract farming in the country with deteriorating soil health.

There will be an investment of Rs 1 lakh crore in the dairy sector alone in the next 7-8 years. This will create 72 lakh new employment opportunities. By the year 2030, the food market will increase more than three times.

Dr. RS Sodhi
President, Indian Dairy Association, former MD, Amul

According to Dr. Harsh Kumar Bhanwala, former Chairman of NABARD and Chairman of MCX, currently 30 percent of the farmers are those who do not own their fields. They do farming by taking land on lease or share-cropping basis. Sharecroppers who take land on short-term contracts are not serious about the health of the land because they have a short term commitment to the piece of land they are tilling. In such a situation, it is being suggested to keep the Land Lease Act as a policy priority. Such an act can give assurance to the land owner that his ownership rights will not be affected and the land can be available to the sharecropper for farming for a long time. A Model Land Lease Act has been prepared by NITI Aayog which is pending with the Ministry of Rural Development for long .

The second big factor is water. Many areas of the country have turned into dark zones due to excessive groundwater exploitation. This situation is more prevalent in areas where the Green Revolution has been successful. The solution to this can also be found at the policy level, but that is possible only through a comprehensive policy which includes assurance from crop diversification to incentives and marketing to the farmers. In view of the crisis of climate change, it is necessary to move towards crop diversification , with a practical approach.

There is continuous talk of labour. An army of unemployed youth is rising in the country but they are running away from agriculture, hence future policy provisions are necessary reverse the trend. KRIBHCO

Photo: Unsplash.com

To create a developed India by the year 2047, it is necessary to increase the growth of agriculture. There is a need for good roads, electricity, water, better internet connectivity with the market in the villages.

Dr. Harsh Kumar Bhanwala
Chairman of MCX, former Chairman, NABARD

Chairman Dr. Chandrapal Singh Yadav says that today there is no attraction among the youth towards farming. This attraction will increase when farming becomes profitable. His suggestion is that the youth should join the cooperative and do farming using new technology , add value to the produce. This way, they would not only be providing employment to themselves,but also to to others. For this, the government should help in creating the infrastructure of the cooperative.

Along with this, possibilities of retaining women in agriculture sector will also have to be explored. They play a major role in the farms and allied sectors like dairy farming. . According to the latest labor force survey, most of the working population of the country works in the agricultural sector. At one time this level came down to 42 percent but due to reduction in employment opportunities in manufacturing it has reached at 45 percent again. In fact, when economic liberalization took place through the new industrial policy in 1991, there was a strong belief that industrial development in the country would accelerate and a large part of the population would leave agriculture and move to industries, due to which the burden on agriculture would reduce and rural India would become prosperous.

It is true that in the meantime urbanization has increased , but it has not been proven that a large number of people dependent on agriculture will reduce. On the other hand, the dream of making India a manufacturing hub has not been fulfilled. The government has been implementing various schemes to take manufacturing's share in Gross Domestic Product (GDP) to 25 percent and has been giving incentives worth lakhs of crores of rupees every year. But it is still stuck at 12 to 13 percent. On the other hand, after reaching about 14 percent, the share of the total number of working people is now around 11 percent according to the Labor Force Survey. The Economist estimates that an industrial growth rate of six percent would have increased employment opportunities by only one percent. The use of automation and technology in manufacturing is continuously increasing. In such a situation, if the agricultural sector grows rapidly, then more employment opportunities will be created here and it can be a more productive employment. Besides, there is huge potential for improvement in the quality of employment in the agriculture sector due to increasing use of technology.

The next factor is energy. For this, farmers are moving away from traditional farming done by oxen and have started using all modern machines including tractors. Tractors, diesel pumps and power tube wells are everywhere now. Not only this, irrigation facilities are developing rapidly using solar power. In the case of energy, farmers need certainty in its rates because increase in its cost directly means increase in the production cost for them.

As far as technology is concerned, genetics is of utmost importance

in agricultural production and agricultural growth rate. Genetics decide the quality of the seed. What is the productivity and what kind of diseases and pests does it have the ability to fight? In such a situation, traditional and modern techniques available in genetics should be used to develop and refine seeds and plant material. In this, if the use of technologies like genetic modification and gene editing ensures better productivity and crop protection, then there should be no delay in adopting it. In an interview with Rural Voice, NITI Aayog member Professor Ramesh Chand has said that we should adopt GM technology in those crops where traditional technology is not successful.

Crop nutrition will have to focus on preserving the fertile elements in the soil and on the fertilizers, minerals and cropping methods necessary to increase its fertility. At the same time, it is important to go beyond selected nutrition products and use whatever products and options are available in chemical and bio-fertilizers. This will require changes in the subsidy policy for approval of new products and their affordable availability. Also, whoever provides better products in this direction in public or private sector should be given a chance. At the same time, it is important to assess the economic benefits of crop nutrition. Overnutrition should be discouraged if it does not impact productivity and economic benefits. But here the policy has to be made transparent.

Today the farmer's son likes to be a peon but does not want to do farming. Attraction towards farming will increase only when benefits are seen in it.

Dr. Chandrapal Singh
Chairman, KRIBHCO

After this is crop protection. The use of pesticides in crops has increased significantly in the last several decades. Besides, the rate at which crop varieties are affected by diseases has also increased. For this, it is necessary to use both chemical and bio-chemical products keeping integrated pest management at the center. But it is also true that the record of our country's companies in developing molecules in agrochemicals is very average. Most of the dependence is on molecules developed abroad and imported materials from there. Besides, a parallel industry of fake pesticides is running in the country. Due to which farmers have to suffer both financially and in the form of crop loss. The government needs to make policy changes on this issue. Also, if success is achieved in crop protection through GM varieties, then it can be taken advantage of wherever possible.

The next and important factor is agronomic intervention. Its scope is very wide. From estimating the cost of the crop to this, marketing aspects can also be added to it. The lack of research and study in our country on this front cannot be denied. If this is implemented properly then it will be beneficial for farmers and agriculture. Data on cost of production from the trial fields of research institutes should be available and there is a need for comparative study of those varieties with production, productivity and cost in farmers' fields.

Photo: Unsplash.com

Agriculture cannot develop without market linkage. Government policies have a big contribution in this. Ethanol blending got a boost only due to policy support.

Roshan Lal Tamak
ED & CEO, Sugar Business,
DCM Shriram Limited

It is also important to talk about the development of the agricultural sector and the possibilities of investment here. NITI Aayog member Professor Ramesh Chand says that only through an agricultural growth rate of 4.5 percent, India can fulfill the dream of being a developed nation by 2047. In such a situation, there is a better opportunity for the government to decide its economic policies keeping agriculture at the center. Although this is not happening right now, it is necessary to do so because there is huge potential in the agriculture sector which can accelerate the pace of development of the country. But for that there will have to be changes in the policies related to agriculture sector and better opportunities will have to be created for investment.

The worrying thing is that the private corporate sector has very little investment interest in the agricultural sector and that too is less than three percent. Most of the investment in agriculture sector is either public investment or farmers' own investment. This situation cannot accelerate the wheel of agricultural development. The central and state governments are giving a large part of the amount allocated for the agriculture sector in their budget in the form of income support or subsidy, while their capital expenditure is negligible. In the current year's Union Budget, the capital expenditure for agriculture is less than Rs 100 crore whereas the government has made a provision of capital expenditure of Rs 11.11 lakh crore. The largest part of this is going on the development of infrastructure facilities. Not only this, government expenditure on agricultural research and education is either stable or decreasing.

DN Thakur, national president of Sahakar Bharati, advocates the creation of a sovereign fund to overcome the capital problem of farmers. Through this fund, guarantees should be given to banks so that they can easily give loans to farmers. He says that cooperative institutions at the village level should be made so capable that their members can purchase every grain from every farmer at the minimum support price and they do not face any problem in selling their produce. In such a big country, there is a need to adopt different models of cooperative.

If all the issues highlighted above are part of an overall agricultural policy, then the economic potential of the agricultural sector can be exploited. The price and marketing structure of agricultural products is as important as production. For this, there is a need to keep the farmer's income at the center. There is a need to change the policy of domestic production, market availability, prices and import and export of crops by keeping the consumer at the centre. The most talked about issue here is that in the matter of Minimum Support Price (MSP), the thinking will have to focus on giving this price to the farmers and the perception of keeping low price at the center for the consumer will have to be changed.

Growth opportunities in agriculture must be explored

Prof. Ramesh Chand

The author is
Member, NITI Aayog

At the time of India's Independence, Russia had a system of collective farming, China had a commune system. It provided for the combined cultivation of all the farmers' land. It did not contain the individual land of a farmer. Our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, wanted such a system in India. Chaudhary Charan Singh wrote a book in opposition to that policy: Joint Farming X-Rayed. He believed that India's farmers are more connected to the land than their children.

No matter how much you tell them about the economic benefits of collective farming, because of the mother-son relationship with the land, they will never be ready for it, nor should we attempt it. He also gives good arguments in favour of it in the book. This also shows his vision towards agriculture. also how he viewed agriculture, peasants and the rural system. His words are still relevant after all these years. He advocated for rural development with the rural cottage industry in focus, which is what we are talking about again today. Today we are emphasizing on agriculture-industry linkages.

To make agriculture the engine of economic growth, we have to think around agriculture in terms of the environment around agriculture. If we think away from that environment, there will be a paradox and not much success. If we move our sector according to time and circumstances, there will be more chances of success and there will be no stalemate. We hear every day that the country's agenda is a developed India. The goal of developed India will only guide the country's priorities furthermore. The Prime Minister has also asked the NITI Aayog to formulate a vision that India of 2047 should be a developed India. The country is moving forward on two things. One is to make the country developed and the other is to make it developed with the participation of all.

To achieve the goal of a developed India, our economy needs seven to eight per cent growth in output over the next 24 years. If we continue at this rate for so many years, our per capita income will be enough to be called a developed country. According to the World Bank, a country with a per capita income of $12,000 i.e. Rs 10 lakh or more can be called developed. Currently, the per capita income is around Rs 1,70,000. We have to multiply it 6 to 7 times in 24 years. The country has decided to follow this path of development and all policies will be formulated around it.

To achieve such growth for 24 years all activities have to be included, be it agriculture, industry or services. But in my opinion, the agricultural sector has the greatest responsibility. There are many reasons for this. We divide the economy into 12 parts and the largest is the agricultural sector. Manufacturing is now close to that. Agriculture accounts for 18 to 20 per cent of the country's income. If the segment with such a large share does not grow at a rate of 3.5% to 4% per annum, it will be very difficult, may even be impossible, to achieve the goal of developed India. Therefore, the role of the agricultural sector is important. It will not succeed in achieving the dream of a developed India without ensuring a high growth rate.

This is nothing to be disappointed about. When you set a goal, you look for ways to reach it. If the growth of the agricultural sector is not up to the desired level, the country will still develop, but we will not get the growth we want in the country - one sans poverty, malnutrition, people not going hungry to bed and development being inclusive. Forty percent of the population may have a higher income, but the rest remain the same. That growth will not be inclusive.

The question is whether it can play the role we expect the agricultural sector to play. I am an optimistic person and I think there is no reason why the agricultural sector will lag behind its role in developing the country. But for that we have to change our perspective. I come from a farming family, so I have an emotional connection to the agricultural sector. In my opinion, first of all, we should change our attitude towards the agricultural sector from negative to positive. That doesn't mean I should close my eyes that there isn't a problem or challenge there. There are problems there, but also great opportunities. I can give dozens of examples of this.

Some of our states have been growing so fast in the agricultural sector for 20 years that there is not as fast growth even in the non-agricultural sectors. Andhra Pradesh, Telangana, Madhya Pradesh are examples. The growth rate of agriculture in these states is more than six per cent. There industry growth is not so much. From there comes a confidence that if these states can achieve agricultural growth at the rate of 6-7%, why can't we adopt their policy and take agriculture beyond this growth rate across the country. This example is not of one farmer, one village or one district, it is the example of the whole state and they are all big states. This gives us the confidence that agriculture can be the engine of economic growth if the right policies are put in place.

Sometimes the question is raised that the condition of agriculture is bad, farmers are committing suicide. I would like to give an example with full empathy. If a village has 1,000 youth and 5-10% of them are malnourished or sick for some reason, wouldn't that village try to prepare sportspersons? We can change the fate of 80-90% of people by taking the right steps. But these things must not just be said, they must also be made a reality. I would like to draw your attention here to a couple of things about how it is possible to have a high growth rate in agriculture for a long time. The agricultural sector has been and will continue to be a major source of employment.

The question is where the growth opportunities in agriculture will come from. There are many regions where productivity is still very low. In Assam, for example, the average productivity of cows and buffaloes is less than two litres per day. From this you can guess that if the two litres holder wants to come to the 8 litres level like in Punjab or Haryana, there is a 400% growth opportunity for him. Similarly, look at the productivity of another crop. Somewhere you will find that we harvest 18 to 20 quintals of wheat per acre and there are many areas where we can get only 6 to 7 quintals of wheat. Similarly, there are possibilities in other crops, cattle, fisheries, agro-forestry.

Another opportunity is arising in quality food. You may have noticed that in many places in the villages, milk is sold at Rs 35 to Rs 40 per litre and sometimes at Rs 200-300 per litre. You can double to triple your income by producing milk. There are a lot of consumers in this country today who are willing to pay the price for quality. It's not just about milk. You should also look at rice. It sells for Rs 30 per kg and over Rs 100 per kg also. Thus we see that there are quite a lot of possibilities regarding quality. New kinds of demands are emerging in agriculture.

Agriculture is no longer just a means of food, but now people are using it to maintain their health and ward off diseases. Soaps, toothpastes and a lot of industrial products are also now made of bio varieties. There are also possibilities in green credit. The government has recently announced this. There is an opportunity to use solar energy. Even tourism possibilities are coming up in the agricultural sector. Many people are so tired of living in the city that they want to move to the village. But for all these we have to spread the positive and use the resources of development.

Minimum Support Price (MSP) has its own significance. I told the parliamentary committee the other day that in many places if you ensure MSP, the growth will double. Uttar Pradesh is one of them. There are many states where no matter how much you pay MSP, there will be no growth. There's saturation, something else has to be done there. But there are states where MSP is not available. There, if you give MSP, the growth rate will double.

Growth will be even faster if farmers have access to markets. Several steps have been taken in this direction as well. There was also an attempt to break the nexus of middlemen, but from the understanding of some farmer brothers, that was probably not right. You may have heard of Open Network Digital Commerce (ONDC). Just as an industry person can sell their product on Amazon or any other platform so can a farmer, farmers organization or anyone else sell their product online on ONDC.

You give information about the quantity, quality, price etc. on the website. Whoever needs he will see on the website and buy without any middleman. I reviewed it the other day. I find this to be the most disruptive technology. Similarly, the cooperative sector should play a role, which has been limited to the dairy sector right now. Even where cooperatives are not doing well, the dairy sector is doing well. The new Ministry of

(Article is based on the keynote address at RURAL VOICE AGRICULTURE CONCLAVE and NACOF AWARDS 2023)

According to the World Bank, a country with a per capita income of Rs 10 lakh or more can be called developed. Currently, it is around Rs 1,70,000. We have to multiply it 6 to 7 times in 24 years. The country has decided to follow this path of development.

Bringing agriculture back to the centre of policy making

Pravesh Sharma

The writer is Director, Samunnati Agro & former agriculture secretary, Madhya Pradesh

Four simultaneous crises have engulfed Indian agriculture. The first and foremost is an income crisis, with stagnant or falling incomes of farm households, which in turn leads to an investment crisis on the family farm. The second is a factor crisis, of degrading natural resources, especially of soils and water. The third is the accelerating human resource crisis, as the younger generation across states loses faith in agriculture as an attractive employment option, and seeks to escape to urban or even foreign locations for alternative livelihoods. To add to this brew is the rapidly developing climate crisis, which threatens our hard-won food security.

A common thread among the four crises is the almost complete lack of clarity on a coherent and coordinated policy response to address the multifaceted challenges facing the sector. While there may be the views for or against the three farm laws promulgated by the Central Government in 2020, the fact remains that the fierce resistance to the laws by large sections of the farming community, which led to their abrupt withdrawal, also marks the moment when serious policy attention to agriculture more or less stopped. It is true that ongoing programs have continued uninterrupted and the overall food economy continues to see vigorous government action of a tactical nature. However, the public has no clue about any long term planning or guidance to address the several unattended policy challenges outlined above.

A brief look at our own history of how food security was achieved gives us some clues about what needs to be done. It is worth recalling how India travelled from a severely food deficit country, which produced barely 50 million MTs of foodgrains in 1950, to a situation where the tentative estimate of last year's food output is over 330 million MTs. By any standard, this is one of most remarkable achievements of independent India. An agricultural sector which was completely devasted by over a century of extractive British policies was revived over barely three decades, with the adoption of far-sighted policies by the Union and State governments, the dedication of agricultural scientists, hard work by field administrators and, above all, the willing and eager participation of the farming community in adopting complex new technologies and farm management systems.

The so-called Green Revolution broadly describes a holistic ecosystem development approach, which was adopted to modernize Indian agriculture and achieve food security. This ecosystem consisted of an elaborate network of research institutions, extension machinery, credit and input supply channels, marketing and procurement infrastructure and a nation-wide public distribution system, to permanently eradicate chronic food shortages and the spectre of famines. Much of the heavy lifting for this ambitious project was undertaken by the Central government but States backed these efforts whole-heartedly. In fact, the lack of ownership, pride and often ignorance about the epochal achievement of national food security among many of the current generation of political leaders, policy makers, scientists and administrators is one of the abiding puzzles of our times.

Three major lessons emerge from this brief review of the achievements of the Green Revolution phase:

i. A set of policy objectives was clearly defined and an ecosystem, holistic approach was adopted to address these objectives.

ii. The Centre and the +States worked in close coordination over a prolonged period of almost three decades, with each focusing on its assigned and agreed set of roles and responsibilities.

iii. Knowledge was the basis of policy formulation, with great attention being paid to high quality research in the central and state governed institutions, as well as building a robust data gathering and monitoring framework.

Can the success of the Green Revolution era provide some guidance on the way forward? I would argue that instead of reinventing the wheel, we should redeploy the learnings of that earlier phase, which brought us success in achieving the vital goal of national food security.

Three ideas are put forth for discussion and consideration in this regard:

1. The first and foremost requirement is to re-establish a relationship of trust and cooperation between the Centre and the States, to address the next wave of policy challenges in agriculture. Without this key pillar of the ecosystem being repaired and strengthened, it is unlikely that we can achieve optimum outcomes in terms of policy goals. There is currently no standing mechanism at the apex political level, either at the Centre or in the States, where agriculture policy challenges and options can be discussed in an atmosphere free of political grandstanding. We need the equivalent of the GST Council in the area of agriculture, preferably chaired by the Prime Minister, or at least the Union Agriculture Minister. This one step will be a significant break from the policy drift of the past two decades and focus national energies on the urgent task of rebuilding our agriculture ecosystem.

2. The second part of this triad is to identify the broken parts of the agriculture ecosystem, from research to extension, from financing to rural infrastructure and from technology to marketing. An integrated view of various agri value chains and India's desired place in global markets can form the basis of investment, research and skilling, infrastructure building etc. A major change from over fifty years ago, when the Green Revolution was being rolled out, is the growth of private sector capacity and interest in the sector. This can be leveraged successfully to rapidly repair the potential of the ecosystem to respond to the current set of challenges, especially value addition and consequent rural employment creation.

3. The third and equally important aspect of this new phase should be a highly decentralised approach to planning and implementation, with local land tenure systems, food and nutrition status, agroclimatic situations and the impact of climate change being factored in. To this end, research, extension and implementation capacity would have to be fostered within states and sub regions of states. The farming community is today far better informed and aware than was the case in the 1960s and 70s, which to an extent required highly centralised planning and investment, led by scientists and administrators, with little space for incorporating the inherent innovation and wisdom of the farming community. This time around the farming community has to be given a far more active role in planning and execution, making it a partner, not a passive recipient, of policy making.

While the above is a high-level set of principles to address the four crises of agriculture we spoke of at the beginning of this piece, this is by no means an exhaustive or even exclusive set of options. What is essential is to recognise the universality and integrated nature of the challenges facing agriculture, and that solutions are only possible by thinking of the country as one unit. Political contestation, the life-blood of a democracy, can and must continue, but food and nutrition security cannot be an area of division. The time to act is now.

It is worth recalling how India travelled from a severely food deficit country, which produced barely 50 million MTs of foodgrains in 1950, to a situation where the tentative estimate of last year's food output is over 330 million MTs

Hailing Bharat Ratna to Dr MS Swaminathan

Dr. R S Paroda

Former Secretary, DARE & Director General,ICAR and Chairman, Trust for Advancement of Agricultural Sciences(TAAS)

(Padma Bhushan Awardee)

The recent announcement by Hon'ble Prime Minister Shri Narendra Modi to confer Bharat Ratna to Dr MS Swaminathan, Father of Green Revolution in India, has been hailed by the entire agricultural scientific community. Also to pronounce him as Farmer's Scientist is most befitting as he worked all through his life for the welfare of the farming community. He is perhaps the only distinguished person who received all prestigious civilian awards: Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan, and now the Bharat Ratna.

Thanks to his dynamic leadership and invaluable contributions, India has her head high, meeting the domestic food demand despite having emerged as the most populous country in the world.

Today, we have become a major exporting nation. Dr Swaminathan's contributions to strengthen National Agricultural Research System, first Director General of reorganized Indian Council of Agriculture Research, having gained the status of Secretary, Department of Agriculture Research and Education, creation of agriculture research service and many reforms would all be remembered with great admiration. He had been the most decorated agricultural scientist globally.

Dr Swaminathan was the recipient of the first World Food Prize in 1987. He also received the Magsaysay award for community leadership in 1971 besides being the recipient of Albert Einstein World Science Award in 1987; the Indira Gandhi prize for Peace in 1994; UNEP Sasakawa Environment prize in 1994; the UNESCO Gandhi Gold Medal in 1999 and many more. He was also the President of Indian Science Congress and Chairman, FAO Council. He also served as Director General of International Rice Research Institute (IRRI) and was the Founder Chairman of M S Swaminathan Research Foundation, Chennai.

The void created by him will be very difficult to fill as he had been a visionary, a good planner, great human being and above all the most respected by the country for his recommendation as Chairman Farmers' Commission to give farmers MSP 50% higher than cost of cultivation + C2. The entire farming community is grateful for his love for the peasants and Indian agriculture.

The entire agricultural scientific community is pleased that Dr Swaminathan's contributions for household food and nutrition security and this has been recognized through conferment of Bharat Ratna, the highest national honour. We wish it had come when he was alive.

Dr Swaminathan was a Mahanayak, a legend, a great visionary, a policy maker, and a human being par excellence. He was a great son of India. He was also instrumental in the creation of the All India Agricultural Research Service (ARS), which facilitated collaborative research efforts among scientists from all corners of the nation.

His pioneering work to make the country self-sufficient in foodgrains, by introducing and breeding dwarf wheat varieties, had led to enhanced production from 50 million tons in 1950 to now 330 million tons. Hence, from an importing country India became a net exporting nation in the world.

His commitment to bridge the gap between scientific discoveries and practical implementation led to the inception of the Lab-to-Land Program. This visionary initiative sought to transfer agricultural technologies directly to farmers, ensuring that the benefits of research reached those toiling in our fields. It was a testament to his dedication to the welfare of India's farming community. Throughout his distinguished career, he made outstanding contributions in agriculture nationally and internally.

Prof Swaminathan's influence and leadership extended beyond India's borders. As Director General, International Rice Research Institute (IRRI) in the Philippines from 1982 to 1988, he guided the institute to significant strides in rice research, benefiting the rice growing regions worldwide. He was the President of the Pugwash Conferences and the International Union for Conservation of Nature. In 1999, he was one of three Indians, along with Mahatma Gandhi and Ravindra Nath Tagore, on Time Magazine's list of the 20 most influential Asians of the 20th century.

The awards and accolades he received during his lifetime bear witness to his exceptional contributions. From being the first World Food Prize laureate in 1987 to the Shanti Swarup Bhatnagar Award, among others, further highlighted his exceptional dedication to agriculture and rural development.

Prof Swaminathan was a great statesman who tirelessly advocated for the welfare of our farming community. As Chairman of the Farmers Commission, he convinced the Government to come up with the National Farmers Welfare Policy and recommended paying farmers MSP +50% of cultivation cost +C2. For these, he earned high respect from the farming community. His love for the peasants and Indian agriculture was unwavering. I hope that his dream to have a forward looking National Farmers Welfare Policy will be approved by Parliament at the soonest possible.

Excellence with relevance, vigour with rigour, science for society, and quality with humility had been the invaluable lessons throughout his life. I am sure his achievements will continue to inspire the young generations to strive for a better future for Indian agriculture.

Dr Swaminathan was a Mahanayak, a legend, a great visionary, a policy maker, and a human being par excellence. He was a great son of India.

Charan Singh wanted quota for farmers, land reform in their favour

Harvir Singh

The author is Editor-In-Chief, Rural world

Former Prime Minister Chaudhary Charan Singh is one of the few leaders whose politics was centered around farmers. He had done many works in the interest of the farmers. He was the only leader who had prepared the ground for creating a middle class of peasants. Three laws implemented by him in Uttar Pradesh proved to be radical changes in the situation of agriculture and farmers in the state.

He understood the pulse of rural India well, so he advocated 50 per cent reservation in government jobs for children from peasant families to bridge the gap between the urban class and the village and peasantry. He also wrote a paper on it. Acknowledging changes over time, he also amended this paper of 1939 in 1960 to 60 per cent reservation for peasant families and 75 per cent reservation for landless families dependent on agriculture.

The farming middle class that he was talking about is in crisis at the moment. We saw a glimpse of this in the form of the peasant movement on the borders of Delhi in 2020-21. Its sequel could be seen in the next few days as the reality of farmers caught in a cycle of declining incomes and rising aspirations is before everyone's eyes. Leaders like Chaudhary Charan Singh, who had the ability and thinking to change their lives from the fourth decade to the ninth decade of the last century, were not only in politics but were in governments and had the ability to make and implement laws for them. Ironically, today there is no politician or farmer leader to fill the void created by him.

Paul R Brass's two-volume book on the political life of Chaudhary Charan Singh is not only an important document, but it brings to light everything from his working style and his correspondence between politicians to the decisions of government departments. Advocating reservation, Singh says there are officials in the agriculture department who cannot distinguish between barley and wheat plants. These people do not know which crops need irrigation when.

He wrote a paper on March 21, 1947, entitled Why Farmers' Children Should Get 60 Percent Reservation in Jobs. In it, he clearly stated that sons and dependents of farmers should be given reservation in government jobs and publicly funded educational institutions. It does not mention any caste.

If we look at it now, castes like Jats, Marathas, Kapu and Patels, which are dependent on agriculture, keep agitating for reservation as their economic and social status has been weakened considerably compared to the urban class. It is different that a large section of the castes who benefited from the laws he enacted in Uttar Pradesh got reservation from the recommendations of the Mandal Commission implemented in August 1990.

Chaudhary Charan Singh was the Home Minister in the Morarji Desai government that constituted the Backward Classes Commission in January, 1979 under the chairmanship of BP Mandal. It was on the basis of the report of this commission, that the provision of 27 per cent caste-based reservation for Other Backward Classes (OBCs) was implemented in August, 1990. SCs and STs already get 22.5 per cent reservation.

Citing a 1961 survey, he said the share of people from peasant backgrounds in the Indian Administrative Service (IAS) was only 11.5 per cent, while the share of children of government employees was 45.8 per cent. In this regard, he said that the children of farmers should get 60 per cent reservation. Also, children of people who have availed government jobs should be considered ineligible for government jobs.

He argued that this would increase the efficiency of government departments as farmers' children are better at work and also able to take better decisions in difficult situations. His hands will not tremble in taking a tough decision like an official coming from an urban background. He will prove better than the tehsildar who fixes a dozen dates for the hearing of a case of compensation of Rs. 100.

In fact, he was of strong view about the difference between villages and cities. He believed that the real difference was between the village and the city. Urban people think of villagers as rustic and ignorant. This is the case when in 1950-51, the share of agriculture in the gross domestic product (GDP) of the country was 54 percent and 70 per cent of the people of the country depended on agriculture for employment. Reservation is necessary to close this gap, as government jobs are currently occupied by urbanites. Farmers and villagers are suffering from poverty due to lack of opportunity. He also made it clear that no one should be asked about his caste when entering government jobs and educational institutions.

The first proposal for reservation for children of peasants was put before the Executive Committee of the Uttar Pradesh (then United Provinces) Congress Legislature Party in April 1939, calling for 50 per cent reservation. When he was criticized for his opinion of excluding landless people from the reservation, he said that he had no objection to that and that the reservation should be increased to 75 per cent.

According to the 1951 census, the share of these people engaged in agricultural activities was 28.1 per cent. He never tried to show himself as a Jat of his caste, but worked for all the peasants. This is why he formed an alliance of Muslims, Ahirs, Jats, Gurjars and Rajputs (Majgars) as a political force.

Talking about the three laws of Chaudhary Charan Singh, the first is the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act (ZALR) 1950, which took land from the zamindars and gave its ownership to the sharecroppers who cultivated it. This law of 1950 changed the fate of the farmers of Uttar Pradesh. All the efforts of the landlords failed and the cultivators became the owners of the land. By this law the system of landlords paying taxes to the government for cultivation was abolished for ever.

While the farmers became the owners of the land with ancestral rights, the Yadavs, Kurmis, Gurjars, Muslims and all backward castes benefited the most from this law.

The UP Consolidation of Holdings Act, 1953 was the second law. Under this law he wanted those who got land after the old system was changed to become more efficient

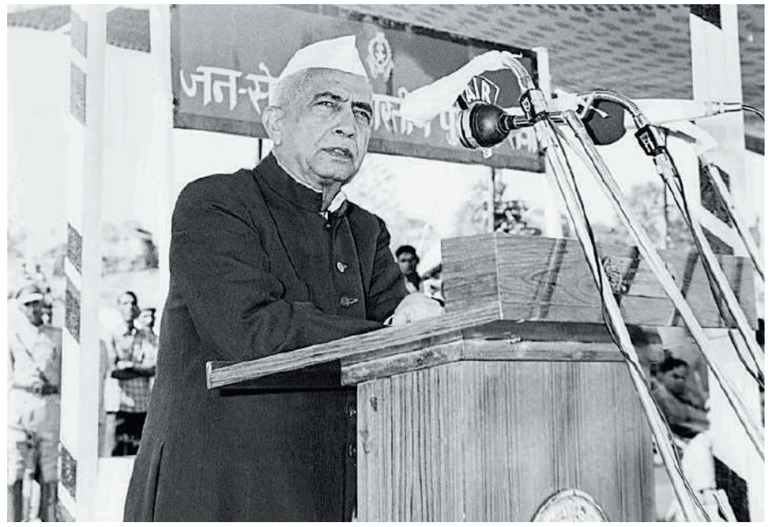

farmers. For him, farmers' holdings in different places were brought together so that his entire holdings were in one place. This will increase his productivity and efficiency. In 1976-77, out of 146 lakh hectares of land in Uttar Pradesh, 142 lakh hectares of land had been demarcated under the Act.

Then the third law, the UP Imposition of Ceiling on Land Holdings Act, 1960, followed. Under this law, a limit of 40 acres of better quality was fixed for a family of five persons. He believed that a minimum to maximum size of a farmer's holding of two and a half acres to 27.5 acres was ideal. In it he can farm himself with his family and also use productivity enhancing machines including tractors.

With these laws of Chaudhary Charan Singh, the farmers benefited from the Green Revolution. Provisions like higher productivity crop varieties, availability of fertilizers, government procurement under the MSP system raised a large middle class of farmers.

This feat, achieved in early four decades ago, has now become history. Stagnating yield in areas where the green revolution has worked, shrinking holdings as land is fragmented, rising input costs and abnormal weather changes have changed the situation. The rural India, the farmer and his family are in crisis. A national level farmer leader with the vision and ability to lead policy changes to get them out of this crisis no longer exists.

The announcement of Bharat Ratna to Chaudhary Charan Singh has once again given an opportunity to understand his policies and steps and review the farmers' crisis at a time when there is no big holistic solution to end their problems.

Bharat Ratna

Charan Singh's greatest contribution
Resistance to collectivization

Ravi Shanker Kapoor

The author is a freelance journalist

In India, success and often even greatness in politics is measured in terms of the importance of rank and station: which office a politician holds, the duration for which they hold that office, and so on. The metrics are patently wrong; for example, Mahatma Gandhi and Jayaprakah Narain never ran any government, but they were as important as any viceroy or prime minister in the twentieth century. Therefore, Charan Singh, who was recently awarded Bharat Ratna by the Narendra Modi government, should not be judged just by his place in the power structure but by his achievements. And his biggest achievement was his successful fight against the evil of collectivization of agriculture.

Encyclopedia Britannica defines collectivization as the "policy adopted by the Soviet government, pursued most intensively between 1929 and 1933, to transform traditional agriculture in the Soviet Union and to reduce the economic power of the kulaks (prosperous peasants). Under collectivization the peasantry were forced to give up their individual farms and join large collective farms (kolkhozy)."

The consequences were catastrophic: "Output fell, but the government, nevertheless, extracted large amounts of agricultural products it needed to acquire the capital for industrial investment. This caused a major famine in the countryside (1932-33) and the deaths of millions of peasants," according to Britannica.

In China, the results were no different. "In 1955 the Maoists speeded up the process of agricultural collectivization. "After this came the Great Leap Forward, a refinement of the traditional five-year plans, and other efforts at mobilizing the masses into producing small-scale industries throughout China. The experiment's waste, confusion, and inefficient management combined with natural calamities to produce a prolonged famine (1959-61) that killed 15-30 million people."

The horrors of socialism and communism—over 100 million people dead all over the world because of collectivization, purges, mass murders that communist tyrants carried out regularly—came to the fore mostly after the end of the cold war. In the 1950s, the then prime minister Jawaharlal Nehru was fascinated with the utopian promises made by Karl Marx and his followers. This was the reason that Nehru was promoting joint and cooperative farming.

But Charan Singh, who had an agrarian background, knew better. What was more important was that he had the courage to slam Nehru's ideas, for there were other leaders too with their roots in villages but they didn't oppose the dangerous idea of collectivization. This was akin to a BJP leader opposing Prime Minister Narendra Modi on a policy issue, for Singh was a member of the grand old party at that time. He made his views known to all at the Congress' annual session in Nagpur in 1959.

In the same year he wrote Joint Farming X-rayed: The Problem and Its Solution, which present cogent arguments against Nehru's quixotic ideas. "Attachment to the land is a universal trait in the peasantry of all countries. The French peasant, for instance, calls his land his 'mistress'," Singh wrote.

He went on to write, "Human nature is the same everywhere. Here, our peasant calls his land Dharti Mata—Mother Earth—inasmuch as it provides sustenance for all living things. Everywhere the peasant is a firm believer in property striving for independence. Hence a collectivist economy will meet with his emotional resistance from the start. Ultimately it is not a question of economic efficiency or of form of organization, but whether individualism or collectivism should prevail. Peasantry represents not only a certain form of economy but also a certain way of life. Within the peasantry those characters, traits and moral forces are most pronounced which resist the tendency towards collectivism and of being leveled down into a uniform mass."

It is unfortunate that Charan Singh is seen as a leader of farmers who managed to become prime minister for a few weeks. The reason is that people in our country don't know much about, in the first place, the calamities that were brought in the countries where collectivization was introduced and, secondly, the role he played in forestalling the impending catastrophe. Rw

Opinion

16 th Finance Commission: Conservation of Natural Resources

T NANDAKUMAR

Former Secretary
Food & Agriculture,
Govt of India

The 16 th Finance Commission has been notified with Dr Arvind Panagaria as its chairman, with the following terms of reference.

i. The distribution between the Union and the States of the net proceeds of taxes which are to be, or may be, divided between them under Chapter I, Part XII of the Constitution and the allocation between the States of the respective shares of such proceeds;
ii. The principles which should govern the grants-in-aid of the revenues of the States out of the Consolidated Fund of India and the sums to be paid to the States by way of grants-in-aid of their revenues under article 275 of the Constitution for the purposes other than those specified in the provisos to clause (1) of that article; and
iii. The measures needed to augment the Consolidated Fund of a State to supplement the resources of the Panchayats and Municipalities in the State on the basis of the recommendations made by the Finance Commission of the State.

Unlike the 15th Finance Commission's terms of reference, the current notification stays away from all controversial references. This might give the commission adequate space to allocate resources to achieve national priorities. While poverty, population, and geographical area have been used as major benchmarks by earlier Finance Commissions, the 15 th FC had a reference to Forest & Ecology carrying a weightage of 10% .

The 13th FC made a special reference to water conservation and management efforts. A statutory autonomous body at the state level could help in addressing these issues.

We recommend setting up of a Water Regulatory Authority in each state and specification of a minimum level of recovery of water charges. The proposed regulatory authority may be given following functions:

i) To fix and regulate the water tariff system and charges for surface and sub-surface water used for domestic, agriculture, industrial and other purposes.
ii) To determine and regulate distribution of entitlement for various categories of uses as well as within each category of use.
iii) To periodically review and monitor the water sector costs and revenues.

The Commission had allocated Rs 5000 crores for the purpose. This , however, did not make a big impact nor was the effort followed up. In any case, water is only one, though major, component of natural resources.

The rapid erosion of natural resources: soil and water in particular, is causing serious concern. While Policy makers are alarmed at the state of affairs in many parts, farmers are worried about the future of agriculture as well. They do understand that they cannot do much individually. They are , as is obvious in some rural consultations, large policy and schematic interventions from the state to set this right. This could soon snowball into a major concern not only of environmentalists, but of farmers.

India's National and International commitments which include the following have also to be kept in mind:

- Bringing 10 million hectares of land under Natural Farming by 2027
- Restore 26 million hectares of degraded land by 2030 (UNCCD COP 2019)
- Facilitating crop residue management on 4.1 million hectares by 2024 (Outcome Budget 2023-24)
- 33 per cent of India's geographic area to be covered under forests and tree cover (NAPCC 2008)
- Creating an additional carbon sink of 2.5 -3 billion tonnes of CO2 equivalent by 2030 (UNFCCC 2015)
- Achieving carbon neutrality by 2070

It would not be possible to achieve these targets without allocating additional resources to the states.

K P SINGH
Chief Executive Officer,
Hans Heritage Jaggery and Farm Produce

Ground Report

New era of jaggery-khandsari industry through technology & marketing

Due to rapid increase in the number of sugar mills in UP, the jaggery and khandsari industry faced extinction. But with the arrival of new thinking entrepreneurs and technology, there is a possibility of its revival.

Harvir Singh

Sikandarpur, Jhinjhana (Shamli) & Fugana (Muzaffarnagar):

When words like automation, computer control, panel, no human touch, no pollution, smokeless are associated with the jaggery making unit, people suddenly do not believe it, because in their mind conjures up the images of crusher, crusher and juice boiling in open pan. This is the traditional way of making jaggery. This is the reality. Technology and new marketing strategy is opening a new path for the modern form of jaggery industry. Technology is changing the perception of the jaggery industry which is seen as a polluting and unhygienic production process. Not only this, the quality jaggery products made about four decades ago which are chemical-free and retain their nutritional value are also making a comeback. Hygienic and attractive packaging and wide range of products can increase its consumption among consumers in the coming days and can also create new entrepreneurs.

K P Singh, an established name in the field of technology in sugar industry, is the chief executive officer (CEO) of automatic and latest technology based jaggery production plant Hans Heritage Jaggery and Farm Produce setup by his wife at Sikanderpur, Jhinjhana in Shamli district. Singh, who has about 40 years of experience in the sugar industry, has been the Group Technology Head at Balrampur Sugar Mill, one of the largest sugar industry groups in the country. A resident of village Unn in Shamli district, he shared with Rural World his views about jaggery production with new technology and setting up this industry. While taking us on a guided tour in the premises of Hans Heritage Industries plant, saying, "I have learned a lot in the sugar industry. Achieved it. Now my idea is to establish a modern industry in my village so that I can give back something to the society. For this I bought 10 acres of land in Oon so that this plant could be established there. But there is a sugar mill named Rana Sugar in Oon and as per government rules, a power crusher based Khandsari unit cannot be established within the radius of 7.5 km of a sugar mill. Therefore, this plant was established by purchasing three acres of land in Sikandarpur."

Singh says that I wanted to realize the dream of bringing a pollution-free and healthy product to the market by setting up a jaggery production plant through new technology. There is no water pollution in this plant nor do we burn bagasse. That's why there is no smoke. The entire process is automated, hence the jaggery made here is not only hygienic, apart from sucrose, minerals beneficial for health are also present in jaggery. All production is done through electricity received from the grid. For crushing sugarcane, four vertical rollers and crushers of 20 by 30 inches are used. Through this, a capacity of 250 tonnes per day was achieved. It can be taken up to 100 tonnes per day through an additional mill.

He explains that to make jaggery, hot furnace is used for boiling sugarcane juice. For this, a temperature of 65 degrees Celsius is prepared

through a heat pump. Steam of 105 degrees is produced through mechanical vapor recompressor and hot water is produced at 110 degrees. Sugarcane juice is converted into jaggery in a step by step process through hot water pressure pump and steam. Calcium bicarbonate is used to clean the mud and foreign material present in the jaggery and in this process the mud and foreign material remains at the bottom. He says that through this process we are achieving recovery of 16 percent jaggery from sugarcane. It contains 80 percent sugar and 20 percent non-sugar material, which contains most of the healthful minerals. He claims that the moisture level in the bagasse (bagasse) released after crushing in this plant is 45 percent, which is better than any sugar industry in the country. The entire process of running the plant is computerized which is controlled by a team of experts.

By using this modern technology of jaggery production, jaggery has been produced which meets better quality and health standards, but its marketing was not very easy. After starting the production in January last year, when Singh went to the country's famous Muzaffarnagar jaggery market with the first lot of jaggery, the commission agents there were not ready to buy. The reason for this was the color of jaggery which is dark earthy. At that time, the price of jaggery in the market was Rs 32 per kg, but due to the color of the jaggery, the traders were ready to pay only Rs 26 per kg. On the fourth day, when a trader named Shahnawaz tasted jaggery in the market, he said that the jaggery which was made 40 years ago, is as coarse and granular as it was. There will be a market ready for your jaggery, so ignore the traders' advice and make this jaggery. Singh says, after a few days Shahnawaz came to the plant and said that I will try to sell your jaggery. He sent 20 trucks of jaggery to 20 different cities of Gujarat for 20 days. Each truck contained 20 tonnes of jaggery and all the jaggery was sold there. However, due to accumulation of stock of jaggery, the unit had to be shut down for about eight days.

Last year the price of jaggery ranged from Rs 28 to Rs 34. This year too, Shahnawaz is purchasing about 90 percent of the jaggery production but this year he is selling it in Punjab. So far this year, the price has ranged from Rs 28 to Rs 32 per kg. KP Singh is expected to achieve break even this year. Major part of the jaggery being made at Hans Heritage is made up of large cake pieces of jaggery which are sold in 26 kg packing. GST is applicable on jaggery up to the packing of 25 kg, not above that. Along with this, the company is also making jaggery and marketing it in small packs (as in the photo above). It contains half kg and one kg packs of jaggery in nice packaging. Their shape is like chocolate. The strategy of better marketing of jaggery by adding sesame and some other beneficial products is also being implemented so that it can find a place in the shelves of big retail chain stores and can also reach the customers buying high value products.

Singh says, our jaggery has not only met all the standards in the country in the pesticide residue test, it also meets the standards of 200 pesticides tested in America. 400 pesticides are tested in the European Union (EU), it also meets the standards there.

There is no water pollution in this plant nor do we burn bagasse. That's why there is no smoke. The entire process is automated, hence the jaggery made here is not only hygienic, but apart from sucrose, minerals beneficial for health are also present in it.

But the interesting thing is that the companies making Chyawanprash in the country give preference to such jaggery, because it contains up to 95 percent sucrose, which is prepared by mixing sugar. She is buying our jaggery for medicines. Another interesting fact is that according to Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) standards, jaggery should contain 90 percent sucrose whereas in reality jaggery contains only 80 to 82 percent sucrose. A new jaggery and khandsari unit has been set up by Freyr Foods pvt. Limited in Fugana village of Muzaffarnagar district, about 30 kilometers from Hans Heritage. Among the entrepreneurs who founded it is 60-year-old Bijendra Malik who has a master's degree in Agricultural Science. The other founders are Nischay Malik, an MBA from Cardiff University, UK, and Abhishek Malik, a food technologist. Freyr Foods focuses more on product innovation. It cost Rs 3 crore to

set up a plant with a capacity of 150 tonnes per day. In this, six rollers are being used in two 3 by 2 crushers for crushing sugarcane. In this unit, jaggery, khandsari and other value added products are being prepared through mechanization and manual method.

Bijendra Malik, a director of the company, says, we are producing jaggery and khandsari through open pan but we do not use any chemical. During the process of heating sugarcane juice, natural herb Shuklai extract is used to purify the juice. In the current crushing season, we have started crushing from October 20, 2023 and we are taking a recovery of 13 percent.

Yashpal Malik, National Coordinator of All India Jat Reservation Sangharsh Samiti, is the father of Nishchay Malik and it is he who has prepared the concept of this unit. Yashpal Malik told Rural Voice the entire process of the plant and said that here we are making products for retail and wholesale sale. Jaggery and Khandsari are sold in bulk under the Kisan Shree brand. Among the value added products, they are making 9 products like Jaggery Chocolate, Jaggery Gram, Chai Masala Jaggery Powder, Immunity Booster Jaggery, Fruit and Nut Jaggery and selling them in attractive and hygienic packing. We are also making two types of vinegar. Our aim is to establish the jaggery industry as a health product industry. Along with Ayurveda, now modern health advisors are also talking about the health benefits of jaggery and this is a positive aspect to promote our industry.

Sugar mills are also facing competition on the price front of sugarcane. Ishwar Singh, a farmer from Sikandarpur who had come to supply sugarcane to Hans Heritage, told Rural Voice that by selling sugarcane here, he is getting a price of Rs 370 per quintal, which is equal to the State Advisory Price (SAP) of sugar. Hans Heritage is near my village, hence transportation cost and time is saved. Payment reaches my account the same day. There is a provision for payment within 14 days for sugar mills, but in the wool and Shamli sugar mills here, payment has

YESHPAL MAIK
BIJENDRA MALIK
ABHISHEK MALIK
at Freyr Foods Private Limited

Our jaggery not only meets all the standards in the country in pesticide residue test, it also meets the standards of 200 pesticides tested in America and 400 such tests in the European Union. Companies making Chyawanprash in the country give preference to such jaggery, because it contains up to 95 percent sucrose, which is prepared by mixing sugar.

been delayed from six months to a year. In such a situation, Hans Heritage has come as a better option for sugarcane farmers. Rajeev, a farmer who came to sell sugarcane, repeats the same thing.

Singh says that last year we had bought sugarcane at the rate of sugar mills and this year also we are giving the same rate and making the payment immediately.

Bijendra Malik, Director of Freyr Foods pvt. ltd, says that we are giving a rate of Rs 370 per quintal for cash payment on the day of supply, whereas on taking payment after 14 days, we are giving a rate of Rs 385 per quintal. By selling sugarcane here, farmers save an additional amount of Rs 7 per quintal which they have to pay as freight for delivering the sugarcane to the purchase center of the sugar mill.

Yashpal Malik says that we are working on forming Jaggery-Khandsari Manufacturers Association. Its objective is to popularize jaggery and khandsari products as a health product among consumers. Just as NECC popularized egg, we also want to develop and establish this industry as a modern industry by popularizing jaggery and khandsari products.

This opening of jaggery and khandsari units based on new technology and marketing strategy is not only in Uttar Pradesh, a plant of 500 tonne per day capacity established in Lanka, Assam is also based on MVR technology. The first such plant was established in Chalisgaon, Maharashtra, in which a small boiler is being used.

Another interesting fact is that according to Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) standar ds, jaggery should contain 90 percent sucrose whereas in reality jaggery contains only 80 to 82 percent sucrose. Along with Ayurveda, modern health advisors are talking about the health benefits of jaggery.

In the last few years, due to the rapid increase in the number of sugar mills in Uttar Pradesh, the jaggery and khandsari industry had come to the verge of extinction. With the arrival of new thinking entrepreneurs and use of technology, there is a possibility of its revival. Technologists like Singh are not only opening the way for other entrepreneurs in re-establishing the jaggery and khandsari industry through new experiments in technology, product innovation and marketing, but are also providing sugarcane farmers with sugarcane supply and better prices as compared to sugar mills. It is also giving an option for hygienic products and health supplements for consumers.

Interim Budget 2024-25: Nothing new for 'Annadata'

The budget of the Agriculture Ministry increased by only Rs 740 crore. A new strategy will be made to increase oilseed production, a comprehensive program will be prepared for dairy farmers, after Nano Urea, now Nano DAP will be promoted.

Ajeet Singh

Before the general elections, in the interim budget for the financial year 2024-25, Finance Minister Nirmala Sitharaman, while addressing the farmers as Annadata, said that their welfare is the top priority of the Central Government and the country will move forward with the empowerment and prosperity of the farmers.

But do the budget provisions also reflect this sentiment of the government? The budget of the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has increased by only Rs 740 crore. If we look at various departments related to agriculture and rural economy, the total allocation of Ministry of Agriculture, Department of Fertilizers, Ministry of Rural Development, Ministry of Animal Husbandry and Fisheries and Department of Food and Public Distribution is approximately less than the revised estimate for the financial year 2023-24. It has decreased by three percent. In the budget speech, the Finance Minister said that to become self-reliant in edible oils, a new strategy will be prepared to promote the production of oilseed crops like mustard, groundnut, soybean and sunflower. In this, emphasis will be laid on research on high productivity varieties of oilseeds, dissemination of modern agricultural practices, market linkage and value addition. Government and private investment will be encouraged for post-harvest activities such as storage, supply chain, processing and marketing.

After the success of Nano Urea, the government is now emphasizing on the adoption of Nano DAP. Nano DAP will be used on various crops in all agro-climatic zones. In the total interim budget of Rs 47.65 lakh crore, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has been allocated Rs 1,17,528.79 crore for 2024-25, while the revised estimate for the current financial year is Rs 1,16,788.96 crore. The argument can be made that it being an interim budget, major announcements have been avoided. But we should also remember that PM Kisan Samman Nidhi was announced in the interim budget of 2019-20 itself and its two installments were paid to the farmers before the implementation of the Election Code of Conduct. There has been no change in the amount of Rs 60,000 crore allocated for this scheme. Under this scheme, farmers are being given Rs 6,000 a year, which was expected to increase. The budget provision of Rs 60,000 crore for the current financial year in MNREGA, a major source of income for people in rural areas, has been revised to Rs 86,000 crore. There is also a provision of Rs 86,000 crore for the new financial year. The amount of crop insurance scheme has been cut. It has been reduced from the revised estimate of Rs 15,000 crore to Rs 14,600 crore.

The government, along with many experts, also talks about innovation in agriculture to increase the income of farmers, but the allocation for agricultural research has been increased by only Rs 65 crore from the revised estimate of Rs 9876.60 crore for the current year to Rs 9941.09 crore. There has definitely been a significant increase in the amount of PM Agricultural Irrigation Scheme. For this, the provision of Rs 8,781 crore has been increased to Rs 11,391 crore. To protect farmers from price fluctuations in the market, the government had started the Price Support Scheme. In the year 2022-23, a budget of Rs 47 crore was received for this scheme. It has come down to Rs 40 crore in the revised estimates of the current financial year and no provision has been made for it in the next financial year. The government had made a provision of Rs 800 crore (revised Rs 446 crore) in the last budget for the distribution of pulses in the states. But this time even this scheme has not received the budget. The revised estimate of Rs 2200 crore for PM-ASHA has been reduced to Rs 1737 crore in the next financial year. This time a budget of Rs 729 crore has been kept for Kisan Sampada Yojana, which was Rs 923 crore last time. A provision of Rs 955 crore was made in the last budget for the scheme of forming 10 thousand FPOs in the country, which was revised to only Rs 450 crore. It has been increased to Rs 582 crore in the budget.

Despite the noise about natural farming, only Rs 100 crore is estimated to be spent for it out of the budget of Rs 459 crore allocated in the current financial year. Rs 365.64 crore has been kept for this in the next budget. The Finance Minister said that through self-help groups, the government has helped about one crore women to become Lakhpati Didi. Taking inspiration from this success, the target of Lakhpati Didi has been increased from Rs 2 crore to Rs 3 crore. A provision of Rs 500 crore has been made in the budget for the Drone Didi scheme. The Finance Minister said that the Central Government is close to achieving the target of building three crore houses in rural areas under the PM Awas Yojana. Keeping in view the housing needs, two crore more houses will be built in the next five years. The government has increased the budget of the Rural Development Ministry to Rs 1.77 lakh crore for 2024-25 from Rs 1.57 lakh crore last year, an increase of about 12 per cent. However, this is only three percent more than the revised estimate of Rs 1.71 lakh crore.

A provision of Rs 7,447 crore has been made in the interim budget for Krishi Unnati Yojana. The revised estimate for the current financial year is Rs 6,378 crore while the budget estimate was Rs 7,066 crore. Items like edible oil-oil palm and oilseeds, integrated development of horticulture, agricultural marketing are included in this scheme. Referring to the achievements of the government in the agriculture sector, the Finance Minister said that under the PM-Kisan Samman Yojana, 11.8 crore farmers are being provided direct financial assistance every year. Crop insurance of four crore farmers has been done. 1361 mandis and 1.8 crore farmers are getting the benefit of eNAM. The Finance Minister said that 38 lakh farmers have benefited from the Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana and 10 lakh jobs have been created. Rw

Reduction in subsidy amount

The government has made a provision of Rs 1.64 lakh crore in the interim budget for fertilizer subsidy. This is Rs 1.75 lakh crore in the current financial year budget and Rs 1.89 lakh crore in the revised estimate. In this, urea subsidy is Rs 1.19 lakh crore which is Rs 1,28,593 crore in the revised estimate of the current financial year. Nutrient based subsidy is Rs 60,300 crore in the revised estimates for the current financial year while it has been kept at Rs 45,000 crore for the coming financial year. Rs 2,05,250 crore has been kept in the budget for 2024-25 for food subsidy. This is Rs 2,12,332 crore in the revised estimates of the current financial year.

Allocation For Agri Related Schemes

Scheme	2023-24 (RE)	2024-25 (BE)	Difference
PM Fasal Bima	15,000	14,600	(-)3%
Rashtriya Krishi Vikas Yojana	6,150	7,553	23%
PM Kisan Samman Nidhi	60,000	60,000	0%
FPO formation	450	582	29%
MNREGA -	86,000	86,000	0%
PM Gram Sadak Yojana	17,000	12,000	(-)29%
PM Awas Yojana	32,000	54,500	70%
Food Subsidy	2,12,332	2,05,250	(-)3%
Blue Revolution	1,500	2,352	57%
Animal Disease Control	1,500	2,465	64%

(Figures in Rs crores, Source: Budget documents)

PM-Kisan amount increased in Rajasthan

Many big announcements have been made for farmers in the interim budget of Rajasthan government. State Deputy Chief Minister and Finance Minister Diya Kumari, while presenting the interim budget for the year 2024-25, increased the amount of PM-Kisan Samman Nidhi Yojana from Rs 6,000 to Rs 8,000 annually. A provision of Rs 1400 crore has been made for this. The state government has announced a bonus of Rs 125 on the minimum support price (MSP) of wheat at Rs 2,275 per quintal. This will cost Rs 250 crore.

Presenting its first vote on account, the Bhajan Lal government of Rajasthan has announced Rajasthan Agriculture Infra Mission of Rs 2000 crore for the agriculture sector. Under this, works like 20,000 ponds,10,000 km irrigation pipeline, and fencing for 50,000 farmers will be done and new technology like drones will also be made available. The government will provide free education from "KG to PG" (Kindergarten to Post Graduation) to students from low income group, small farmers, sharecropper farmers and farm labor families. Mandi tax on sugar and jaggery has also been abolished. Gopal Credit Scheme has been started on the lines of Kisan Credit Card.

MSP for milk hiked in Himachal budget

Himachal Pradesh Chief Minister Sukhwinder Singh Sukhu, while presenting the budget for the financial year 2024-24, announced an increase of Rs 8 in the Minimum Support Price (MSP) of milk. Besides, the daily wages of MNREGA have also been increased. Himachal is the first state to fix the MSP of milk. CM Sukhu announced to increase the MSP of cow milk from Rs 38 to Rs 45 per liter and the MSP of buffalo milk from Rs 47 to Rs 55 per liter. He said liabilities of all milk cooperative societies would be waived off and Rs 150 crore would be spent on strengthening the infrastructure for milk procurement and processing. A grant of Rs 1200 per cow will be given by the government. A provision of Rs 10 crore has been made under the Sheep Goat Rearing Incentive Scheme. Chief Minister announced to increase the daily wages of MNREGA workers by Rs 60 to Rs 240 to Rs 300 per day.

UP budget targets 5.1pc agri growth in FY25

With farmers in Uttar Pradesh Accounting for a sizeable chunk of voters, the state government has set a target of 5.1 per cent growth rate for the agriculture sector. A substantial amount of Rs 460 crore has been earmarked for three new agriculture-related schemes in the budget. One of the schemes announced by him is State Agricultural Development Scheme with a provision of Rs 200 crore. Another Rs 200 crore has been allocated for the World Bank-assisted UP Agri Scheme, while the third scheme for the installation of automatic weather station-automatic rain gauge in blocks and panchayats has been allocated Rs 60 crore. Chief Minister Khet Suraksha yojna is also being started with a provision of Rs 50 crore. Besides, an outlay of Rs 2,400 crore has been proposed for providing electricity at concessional rates to private tube wells of farmers. The budget for financial year 2024-25 has an allocation of Rs 7.36 lakh crore, seeking to prioritise infrastructure development

Karnataka govt to waive interest on overdue loans

The Karnataka government will waive interest on medium and long-term overdue loans of District Cooperative Central and Primary Cooperative Agriculture and Rural Development banks. This will benefit more than 57,000 farmers, he said presenting the 2024-25 budget in the Assembly. An Agriculture Development Authority headed by the Chief Minister will be set up to facilitate effective implementation of policies related to agriculture and allied activities. To encourage integrated agriculture, various schemes related to the agricultural sector will be consolidated and a new scheme called 'Karnataka Raitha Samruddhi Yojane' will be started this year, the CM Siddaramaiah said. A new programme "Namma Millet" will be started, under which processed millets and value-added millets will be made available at affordable prices. Food parks will be established near airports under Public-Private Partnership.

Peasant movement in European countries

Falling prices of farm produce, rising costs of inputs, heavy-handed regulation, powerful retailers, debt loads and cheap imports. These problems are not unique to Indian farmers. Farmers have been demonstrating in most European countries for several weeks. Some of the problems are country specific, but most of their problems are shared. The new and major shared problem is the Climate Agenda, which sets targets to reduce emissions in the agricultural sector by the year 2030. In recent days, thousands of farmers have moved to the centres of major cities with tractors. They not only parked tractors and caused traffic jams, but also overturned manure on roads, threw eggs, vandalized supermarkets and clashed with police. The attitude of the farmers has made governments of the European Union as well as many other countries to bow down. They have either postponed implementation of many provisions or repealed them.

Harshvardhan Patil Elected President of NFCSF

Former Maharashtra minister, Harshvardhan Patil, was unanimously elected as the President of the National Federation of Cooperative Sugar Factories (NFCSF). In a meeting of the newly elected board of directors, Patil was chosen unopposed for a five-year term, from 2024 to 2029. Alongside him, Ketanbhai Patel was re-elected as the Vice President for a second consecutive term. This announcement follows a special general body meeting where 12 directors were elected to form the board. Jaiprakash Dandegaonkar, the outgoing president, chaired the meeting. Returning Òfficer Mekala Chaitanya Prasad (IAS) officially announced the election of Harvardhan Patil and Ketanbhai Patel, a press release issued by NFCSF said. Outgoing President, Dandegaonkar, extended his congratulations to the newly elected leaders. He also expressed gratitude to all members representing cooperative sugar factories and federations for their support during his tenure.

Bumper kinnow crop worries Abohar farmers

Farmers in Punjab's Abohar region, famous for its kinnow, are worried about not getting the right price for the fruit this year. In Fazilka, farmers staged a demonstration outside the DC office and overturned trolleys loaded with kinnow. To register their protest, the farmers threw the citrus fruits on the road and plied a tractor over them. Several farmers from Abohar, along with farmer organizations, arrived outside the DC office and overturned trolleys loaded with kinnow and drove the tractor over them. In the Abohar region, the price of kinnow is barely Rs 7-8 per kg as sufficient quantity of the fruits is not being procured. This is not even half as compared to Rs 20-25 per kg last year. The farmers are demanding that the price of kinnow should be at least Rs 12 a kg. Punjab has witnessed a bumper crop of kinnow this year. But farmers are frustrated in the absence of right price and buyers for their produce. Farmers are also demanding fixing of minimum support price of kinnow.

Union Agriculture Minister Arjun Munda and Union Food and Commerce Minister Piyush Goyal formally inaugurated the four-day Pulses24 conference organized by Global Pulse Confederation (GPC) and NAFED.

Addressing the conference, Munda said that the Government of India is making continuous efforts to reduce dependence on pulse imports. A roadmap has been drawn up to increase pulse production. India has become self-sufficient in gram and many other pulses. There is a slight shortage in Arhar (tur) and urad. Efforts are being made to achieve self-sufficiency in pulses by 2027.

India to be self-sufficient by 2027: Agri Minister

The agriculture minister said that while seed supply of new varieties of pulses is being increased. The area of lentil has increased by about 1 lakh hectares this rabi season. A portal has been launched for procurement of Arhar. Farmers can register on this portal and sell their produce to NAFED and NCCF at Minimum Support Price (MSP) or prevailing market rate, whichever is higher. Union Minister Piyush Goyal said the government is encouraging farmers to grow pulses and the MSP of pulses has been increased significantly. To promote agricultural diversification and production through pulses, the government is ready to sign five-year contracts for procurement of pulses from farmers through NAFED and NCCF.

1

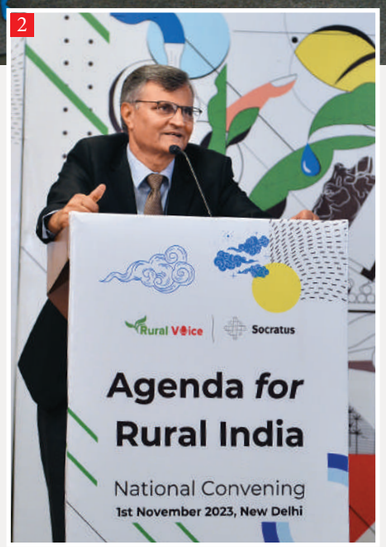

2

एजेंडा फॉर रूरल इंडिया कांफ्रेंस

रूरल वॉयस और सॉक्रेटस ने 'ग्रामीण भारत का एजेंडा' विषय पर देश के अलग-अलग हिस्से में परिचर्चा आयोजित करने के बाद राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय कन्वेंशन आयोजित किया। इस मौके पर एजेंडा रिपोर्ट जारी की गई। इस विषय पर तीन सत्रों में परिचर्चा भी हुई, जिसमें शीर्ष स्तर के अधिकारी, कॉरपोरेट और किसान प्रतिनिधि पहुंचे। इन सत्रों के विषय थे- 1) ग्रामीण भारत किस तरह बदल रहा है 2) ग्रामीण भारत में मीडिया और सिविल सोसायटी की भूमिका तथा 3) निर्वाचित नेताओं और किसान नेताओं से ग्रामीण भारत की अपेक्षाएं।

3

4

5

6

7

8

फोटो परिचय

1. एजेंडा फॉर रूरल इंडिया की नेशनल कन्वीनिंग के मौके पर स्पेशल रिपोर्ट जारी करते कार्यक्रम के अतिथि।
2. मुख्य वक्ता नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद।
3. ग्रामीण भारत कैसे बदल रहा है विषय पर पैनल चर्चा। इसका संचालन रूरल वॉयस के एडिटर-इन-चीफ हरवीर सिंह ने किया।
4. एनसीडीसी के पूर्व चेयरमैन संदीप कुमार नायक।
5. एमसीएक्स के चेयरमैन डॉ. हर्ष कुमार भनवाला।
6. पूर्व कृषि सचिव टी. नंद कुमार।
7. सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. डी.एन. ठाकुर।
8. कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण।

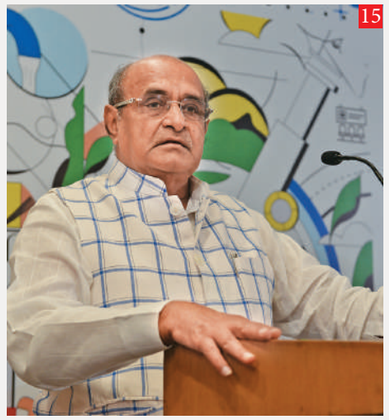

फोटो फीचर

9

15

16

10

11

12

13

14

17

18

19

9. एजेंडा फॉर रूरल इंडिया के दूसरे सत्र ग्रामीण भारत में मीडिया और सिविल सोसायटी की भूमिका पर पैनल चर्चा। इसका संचालन इंडियन एक्सप्रेस के डिप्टी एडिटर हरीश दामोदरन ने किया।

10. खबर लहरिया की सह-संस्थापक कविता बुंदेलखंडी।

11. एसएबीसी के संस्थापक निदेशक भगीरथ चौधरी।

12. शिलांग स्थित संस्था नेसफास की डिप्टी एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर अलीथिया कोरडोर लिंग्दो।

13. ओडिशा के लाइवलीहुड अल्टरनेटिव्स के चेयरमैन संबित त्रिपाठी।

14. तीसरे सत्र- निर्वाचित नेताओं और किसान नेताओं से ग्रामीण भारत की अपेक्षाएं विषय पर पैनल चर्चा। इसका संचालन वरिष्ठ पत्रकार राजेश महापात्र ने किया।

15. पूर्व सांसद और जदयू के वरिष्ठ नेता के.सी. त्यागी।

16. वरिष्ठ पत्रकार राजेश महापात्र और रूरल वर्ल्ड के एडिटर-इन-चीफ हरवीर सिंह।

17. बीजद के राज्यसभा सांसद डॉ. अमर पटनायक।

18. भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय महासचिव युद्धवीर सिंह।

19. एजेंडा फॉर रूरल इंडिया की सह-आयोजक संस्था साक्रेटस की टीम

रूरल वॉयस एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव एंड नेकॉफ अवार्ड्स

23 दिसंबर यानी किसान दिवस रूरल वॉयस का स्थापना दिवस भी है। दिसंबर में इसके तीन साल पूरे होने पर राजधानी दिल्ली में 'रूरल वॉयस एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव एंड नेकॉफ अवार्ड्स' का आयोजन किया गया। शीर्ष नीति निर्माताओं के साथ किसान प्रतिनिधि भी इसमें आए। कॉन्क्लेव में कृषि को इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनाने की थीम पर तीन परिचर्चा सत्र थे। पहले सत्र का विषय 'ग्रामीण क्षेत्र में निवेश और जॉब के अवसर', दूसरे का 'कृषि में उभरते नए सेक्टर' और तीसरे का '2024-29 तक कृषि के लिए गवर्नेंस का एजेंडा' था।

1

2

3

4

फोटो परिचय

1. कॉन्क्लेव के मुख्य वक्ता नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद।
2. रूरल वॉयस एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव एंड नेकॉफ अवार्ड्स का दीप जलाकर शुभारंभ करते अतिथिगण।
3. कॉन्क्लेव में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कराते अतिथिगण।
4. परिचर्चा को सुनते मौजूद दर्शक।
5. ग्रामीण क्षेत्र में निवेश और जॉब के अवसर विषय पर आयोजित पहला सत्र। इसका संचालन रूरल वर्ल्ड के एडिटर-इन-चीफ हरवीर सिंह ने किया।
6. इंडियन डेयरी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉ.आर. एस सोढ़ी।
7. एमसीएक्स के चेयरमैन तथा नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन डॉ. हर्ष कुमार भनवाला।
8. डीसीएम श्रीराम लिमिटेड में शुगर बिजनेस के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर एवं सीईओ रोशन लाल टामक।

5

6

7

8

9

16

17

18

19

20

21

10

12

13

11

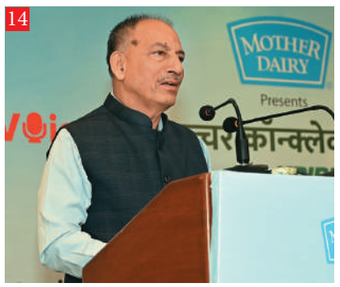

14

15

22

9. फार्मर्स कलेक्टिव एंड न्यू राइजिंग सेक्टर्स इन एग्रीकल्चर विषय पर आयोजित दूसरा सत्र। इसका संचालन जयंत रायचौधुरी ने किया।

10. नेशनल प्रोडक्टिवटी काउंसिल के पूर्व डायरेक्टर जनरल और एनसीडीसी के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर संदीप नायक

11. नेशनल शुगर फेडरेशन एनएफसीएसएफ लि. के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रकाश नायकनवरे।

12. एमसीएक्स के एग्रीकल्चर डिवीजन के हेड अभिषेक गोविलकर।

13. कृभको के चेयरमैन डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव।

14. सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. डी.एन. ठाकुर।

15. कॉन्क्लेव में मौजूद अतिथिगण।

16. गवर्नेंस एजेंडा फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग फॉर 2024-29 विषय पर आयोजित तीसरा सत्र। इसका संचालन इंडियन एक्सप्रेस के डिप्टी एडिटर हरीश दामोदरन ने किया।

17. भारत कृषक समाज के अध्यक्ष अजय वीर जाखड़।

18. राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय संयोजक सरदार वीएम सिंह।

19. एग्री स्टार्टअप समुन्नति एग्रो के डायरेक्टर प्रवेश शर्मा।

20. साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर के फाउंडर डायरेक्टर भगीरथ चौधरी।

21. इकरो के परियोजना प्रमुख डॉ. राजीव रंजन।

22. कॉन्क्लेव में भाग लेने आए किसान प्रतिनिधि।

Awardees

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

23. रूरल वॉयस नेकॉफ अवार्ड के साथ चारों पुरस्कार विजेता।

24. कृभको चेयरमैन डॉ. चंद्रपाल सिंह, नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद, रूरल वर्ल्ड के एडिटर-इन-चीफ हरवीर सिंह, नेकॉफ चेयरमैन राम इकबाल सिंह और आईपीएल के एमडी डॉ. पी.एस. गहलोत। अवार्ड लेते अनार किसान चंद्र प्रकाश माली।

25. अवार्ड ग्रहण करते इफ्को के परियोजना प्रमुख डॉ. राजीव रंजन।

26. अवार्ड लेते साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर के फाउंडर डायरेक्टर भगीरथ चौधरी।

27. साधन सहकारी समिति लिमिटेड निधौली कलां के अध्यक्ष योगेंद्रपाल सिंह सोलंकी ने रूरल वॉयस नेकॉफ अवार्ड ग्रहण किया।

28. कॉन्क्लेव के दौरान परिचर्चा सुनते अतिथिगण।

29. कॉन्क्लेव के दौरान परिचर्चा सुनते किसान प्रतिनिधि।

30. कॉन्क्लेव में भाग लेने आए अतिथिगण आपस में चर्चा करते।

31. कॉन्क्लेव के दौरान परिचर्चा सुनते किसान प्रतिनिधि।

32. कॉन्क्लेव में भाग लेने आए अतिथिगण आपस में चर्चा करते।

कृषि क्षेत्र बनेगा इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन

विकसित भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए गांव-किसान का तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ना जरूरी, इसके लिए कृषि क्षेत्र के विकास की समग्र नीति बनाकर गांव किसान की खुशहाली सुनिश्चित करनी होगी

हरवीर सिंह ● अजीत सिंह

भारत की अर्थव्यवस्था को विकसित बनाने और प्रति व्यक्ति आय को 12 हजार डॉलर तक ले जाने का रास्ता खेत-खलिहानों से होकर ही जाएगा। देश की अर्थव्यवस्था के प्रमुख हिस्सेदार कृषि क्षेत्र की लगातार 4.5 फीसदी की सालाना वृद्धि दर के बिना यह संभव नहीं है। किसान कल्याण के तमाम दावों, नीतियों और आर्थिक उदारीकरण के कदमों के बावजूद देश की 45 फीसदी आबादी को आज भी कृषि क्षेत्र ही रोजगार दे रहा है। कृषि क्षेत्र आर्थिक और रणनीतिक दृष्टि से देश की रीढ़ है और देश का सामाजिक विकास कृषि और किसानों की खुशहाली के बिना संभव नहीं है। इसके लिए कृषि क्षेत्र का मजबूत होना जरूरी है। लेकिन यह रास्ता इतना आसान नहीं है। इसके लिए एक समग्र नीति और उसी के अनुरूप योजनाओं की जरूरत है जो अभी मौजूद नहीं हैं।

यह बहुत ही अफसोस की बात है कि देश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े भागीदार और देश की आबादी के आधे से अधिक हिस्से की आजीविका का आधार कृषि क्षेत्र के लिए अभी कोई नीति ही नहीं है। साल 1998 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार के समय एक छोटा दस्तावेज कृषि नीति के रूप में आया था। उसे एक सिनॉप्सिस के रूप में देखा जा सकता है लेकिन वह कोई समग्र नीति नहीं थी। लेकिन यह शुरुआत भी वहीं रुक गई। इसके बाद टुकड़ों-टुकड़ों में कृषि से संबंधित नीतियां बनती गईं और फैसले होते रहे। अमेरिका जैसी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में जहां 2022 के आंकड़ों के मुताबिक केवल 20 लाख जोत हैं, वहां एक निश्चित अंतराल पर कृषि नीति में बदलाव कर उसे नया रूप दिया जाता है। यूरोपीय यूनियन भी एक निश्चित अंतराल पर अपनी कृषि नीति की समीक्षा करता है। लेकिन भारत में इस पर कोई बात ही नहीं करता, यह कोई मुद्दा ही नहीं है। यहां सबसे अधिक फोकस मार्केटिंग पर रहता है। अगर हम जून, 2020 में लाये गये तीन कृषि कानूनों को देखें तो इनका केंद्र बिंदु केवल कृषि उत्पादों की मार्केटिंग से जुड़े मुद्दे थे।

हमें कृषि में उच्च वृद्धि दर हासिल करने और

वाकई कृषि क्षेत्र में मौजूद संभावनाओं का फायदा उठाते हुए उसे देश की इकोनॉमी का ग्रोथ इंजन बनाना है तो हमें मौजूदा किसानों के लिए कृषि नीति नहीं बनानी है, बल्कि किसानों के बच्चों और उनकी अगली पीढ़ी को ध्यान में रखकर कृषि नीति बनानी होगी। इसका उद्देश्य यह हो कि कृषि से दूर हो रहे किसानों को कैसे कृषि क्षेत्र में बनाये रखा जा सके। यह फिलहाल नहीं दिखता है क्योंकि अधिकांश युवा आबादी कृषि के अलावा दूसरे क्षेत्रों में काम करना चाहती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के पूर्व महानिदेशक डॉ. आर.एस. परोदा लगातार इस बात पर जोर देते हैं कि हमें युवाओं की कृषि में वापसी के लिए नयी सोच तैयार करनी होगी और उनके मुताबिक नीतियां बनाकर लागू करनी होंगी।

पिछले महीने रूरल वॉयस के तीसरे स्थापना दिवस पर आयोजित रूरल वॉयस एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव में कृषि को आर्थिक विकास का संवाहक बनाने से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर कृषि क्षेत्र के विशेषज्ञों, नीति-निर्माताओं और किसान प्रतिनिधियों के साथ संवाद हुआ। इस मौके पर अमूल के पूर्व एमडी और इंडियन डेयरी एसोसिएशन के प्रेसीडेंट डॉ. आरएस सोढ़ी ने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा कि जब भी किसान और शहरी उपभोक्ताओं के बीच एक को चुनने की बारी आती है तो नीति-निर्माताओं का झुकाव अक्सर उपभोक्ता की तरफ होता है। शेयर बाजार का सेंसेक्स बढ़ता है तो उसे तरक्की के प्रतीक के तौर पर देखा जाता है, लेकिन जब सब्जियों या खाने-पीने की चीजों के दाम बढ़ते हैं तो उसे खाद्य महंगाई करार दिया जाता है। वास्तव में, इस सोच और ढर्रे को बदलने की जरूरत है।

डॉ. सोढ़ी का कहना है कि अकेले डेयरी सेक्टर में अगले 7-8 साल में एक लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। करीब 12 करोड़ लीटर दूध की प्रोसेसिंग बढ़ेगी तो इससे 72 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वर्ष 2023 तक फूड मार्केट तीन गुना से ज्यादा बढ़कर 170 लाख करोड़ रुपये का हो जाएगा। आज उपभोक्ता भी अच्छा खाना चाहते हैं। अच्छी क्वालिटी और पोषण के लिए अधिक दाम चुकाने को भी तैयार हैं। इसलिए किसानों को ऐसी चीजों का उत्पादन बढ़ाना चाहिए जिसकी बाजार में मांग है। हमें किसानों को बाजार की इन संभावनाओं को समझने और इन्हें भुनाने में सक्षम बनाना होगा।

असल में कृषि उत्पादन के चार आधार हैं जमीन, पानी, ऊर्जा और श्रम। इनका उपयोग कर बेहतर उत्पादन और उत्पादकता हासिल करने के चार टेक्नोलॉजीकल फैक्टर हैं- जेनेटिक्स, क्रॉप न्यूट्रीशन, क्रॉप प्रोटेक्शन और एग्रोनॉमिक इंटरवेंशन। जमीन के लिए जहां भूमि उपलब्धता अहम है, उतना ही अहम है इसका स्वास्थ्य यानी इसमें उर्वर तत्वों की उपस्थिति और उनका लगातर बेहतर स्तर पर बने रहना। वहीं देश में ठेके पर खेती के बढ़ते चलन को बहुत से एक्सपर्ट मिट्टी के स्वास्थ्य के खराब होने से जोड़ रहे हैं।

अकेले डेयरी सेक्टर में अगले 7-8 साल में 1 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। इससे 72 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। वर्ष 2030 तक फूड मार्केट का बाजार तीन गुना से ज्यादा बढ़ जाएगा।

डॉ. आरएस सोढ़ी
प्रेसिडेंट, इंडियन डेयरी एसोसिएशन, अमूल के पूर्व एमडी

नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन तथा एमसीएक्स के चेयरमैन डॉ. हर्ष कुमार भनवाला के अनुसार अभी 30 फीसदी किसान ऐसे हैं जिनका खेत उनका अपना नहीं है। वे बटाई पर जमीन लेकर खेती करते हैं। कम समय के लिए ठेके पर जमीन लेने वाले बटाईदार जमीन के स्वास्थ को लेकर बहुत संजीदा नहीं रहते क्योंकि उनको लगता है कि इस पर उनका निवेश उनके लिए फायदेमंद नहीं है। ऐसे में लैंड लीज एक्ट को नीतिगत प्राथमिकता में रखने का सुझाव दिया जा रहा है। ऐसा एक्ट जो जमीन के मालिक को यह भरोसा दे सके कि उसके मालिकाना हक पर कोई आंच नहीं आने वाली है और बटाईदार को लंबे समय तक खेती से जमीन उपलब्ध हो सके। नीति आयोग ने एक मॉडल लैंड लीज एक्ट तैयार किया है जो कई साल से ग्रामीण विकास मंत्रालय के पास है, लेकिन राजनीतिक जोखिम के चलते इस पर कोई अमल नहीं हो रहा है।

दूसरा बड़ा कारक है पानी। देश के अनेक इलाके अधिक भू जल दोहन के चलते डार्क जोन में तब्दील हो चुके हैं। यह स्थिति हरित क्रांति की कामयाबी वाले क्षेत्रों में अधिक है। इसका उपाय भी नीतिगत स्तर ही मिल सकेगा लेकिन वह एक समग्र नीति के जरिये ही संभव है, जिसमें फसल विविधीकरण से लेकर किसानों को इंसेंटिव और मार्केटिंक का भरोसा निहित हो। जलवायु परिवर्तन के संकट को देखते हुए भी फसल विविधीकरण की तरफ बढ़ना जरूरी है, लेकिन इसमें व्यावहारिक पक्ष को ध्यान में रखना भी जरूरी है।

साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए कृषि की ग्रोथ बढ़ाना जरूरी है। गांवों में अच्छी सड़कें, बिजली-पानी, मंडी के साथ इंटरनेट की बेहतर कनेक्टिविटी की जरूरत है।

डॉ. हर्ष कुमार भनवाला
एमसीएक्स के चेयरमैन, नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन

Photo: Unsplash.com

श्रम की बात लगातार हो रही है। देश में युवा बेरोजगारों की फौज खड़ी होती जा रही है लेकिन वह कृषि से दूर भाग रहे हैं। ऐसे में युवाओं को कृषि में रोकने के लिए भविष्य के नीतिगत प्रावधान जरूरी हैं। कृभको के चेयरमैन डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव कहते हैं कि आज खेती के प्रति नौजवानों में आकर्षण नहीं है। यह आकर्षण तब बढ़ेगा जब खेती में फायदा दिखेगा। उनका सुझाव है कि युवा कोऑपरेटिव से जुड़कर नई तकनीक से खेती करें, उपज में वैल्यू एडिशन करें तो खुद को रोजगार देने के साथ दूसरों को भी रोजगार दे सकते हैं। इसके लिए सरकार को कोऑपरेटिव का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में मदद करनी चाहिए।

इसके साथ ही महिलाओं को भी कृषि क्षेत्र में बनाये रखने की संभावनाएं तलाशनी होंगी। अब भी देश के कृषि क्षेत्र में महिला किसानों की बड़ी हिस्सेदारी है। ताजा लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक देश की कामकाजी आबादी का लगभग 45 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में काम करता है। एक समय यह स्तर घटकर 42 फीसदी तक आ गया था लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में रोजगार के अवसर घटने के चलते यह फिर बढ़ गया है। असल में 1991 में नई औद्योगिक नीति के जरिये आर्थिक उदारीकरण आया तो यह धारणा बहुत मजबूत थी कि देश में औद्योगिक विकास तेज होगा और आबादी का एक बड़ा हिस्सा कृषि को छोड़कर उद्योगों का रुख करेगा, जिसके चलते कृषि पर बोझ कम हो जाएगा और ग्रामीण भारत में लोगों की संख्या घटने से वहां लोगों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी।

यह बात सही है कि इस बीच देश में शहरीकरण बढ़ा है और शहरी आबादी का प्रतिशत भी बढ़ा है लेकिन बड़ी संख्या में खेती पर निर्भर लोग कम होंगे, यह सही साबित नहीं हुआ। दूसरी ओर भारत को मैन्यूफैक्चरिंग हब बनाने का सपना पूरा नहीं हुआ है। सरकार मैन्यूक्चरिंग को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 25 फीसदी हिस्सेदारी तक ले जाने के लिए तमाम योजनाएं लागू करती रही है और हर साल लाखों करोड़ रुपये के इंसेंटिव देती रही है। लेकिन यह अब भी 12 से 13 फीसदी पर ही अटकी है। दूसरी ओर कुल कामकाजी लोगों की संख्या की हिस्सेदारी करीब 14 फीसदी तक पहुंचने के बाद लेबर फोर्स सर्वे के मुताबिक अब 11 फीसदी के आसपास है। इकोनॉमिस्ट्स का आकलन है कि छह फीसदी औद्योगिक वृद्धि दर रोजगार अवसरों में केवल एक फीसदी का इजाफा करती। मैन्यूफैक्चरिंग में ऑटोमेशन और तकनीक का इस्तेमाल लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कृषि क्षेत्र अगर तेजी से बढ़ता है तो यहां रोजगार की अधिक संभावनाएं पैदा होंगी और यह अधिक उत्पादकता वाला रोजगार हो सकता है। साथ ही तकनीक का इस्तेमाल बढ़ने से रोजगार की गुणवत्ता में भी सुधार की बड़ी संभावनाएं कृषि क्षेत्र में हैं।

अगला कारक है इनर्जी। इसके लिए जहां किसान बैलों से होने वाली परंपरागत खेती से दूर जा रहा है और ट्रैक्टर समेत तमाम आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल करने लगा है। यह बात अलग है कि सभी किसान आधुनिकतम उपकरण नहीं खरीद सकते हैं। ट्रैक्टर, डीजल पंप और पावर ट्यूबवैल अब हर जगह हैं। यही नहीं सोलर पावर का इस्तेमाल कर सिंचाई सुविधाओं का तेजी से विकास हो रहा है। इनर्जी के मामले में किसानों को इसकी दरों में निश्चितता की दरकार है क्योंकि इसकी लागत में बढ़ोतरी का सीधा अर्थ है किसान की उत्पादन लागत में बढ़ोतरी। ऐसे में अगर उसी अनुपात में फसल के दाम नहीं बढ़ते हैं तो किसान घाटे में जाता है।

जहां तक टेक्नोलॉजी की बात है तो कृषि

उत्पादन और कृषि वृद्धि दर में तकनीक की दृष्टि से जेनेटिक्स की अहमियत सबसे अधिक है। जेनेटिक्स ही तय करते हैं कि बीज की क्या गुणवत्ता है, कैसी उत्पादकता है और वह किस तरह की बीमारियों और कीट से लड़ने की क्षमता रखता है। ऐसे में बीज और प्लांट मैटीरियल को विकसित और परिष्कृत करने के लिए जेनेटिक्स में उपलब्ध पारंपरिक और आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें अगर जेनेटिक्स मोडिफिकेशन और जीन एडिटिंग जैसी तकनीक का इस्तेमाल बेहतर उत्पादकता और क्रॉप प्रोटेक्शन को सुनिश्चित करता है तो उसे अपनाने में देरी नहीं होनी चाहिए। रूरल वॉयस के साथ एक इंटरव्यू में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने कहा कि जहां पारंपरिक तकनीक कामयाब नहीं हो रही है उन फसलों में हमें जीएम टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए।

दूसरा अहम फैक्टर है क्रॉप न्यूट्रीशन। इसमें सबसे पहले तो मिट्टी में उर्वर तत्वों को संरक्षित करने और उसकी उर्वरता बढ़ाने के लिए जरूरी उर्वरक, मिनरल्स और फसल पद्धतियों पर फोकस करना होगा। वहीं न्यूट्रीशन के चुनिंदा उत्पादों से आगे जाकर केमिकल और बॉयो फर्टिलाइजर में जो भी उत्पाद और विकल्प उपलब्ध हैं उनका उपयोग करना जरूरी है। इसके लिए नये उत्पादों की मंजूरी और उनकी किफायती उपलब्धता के लिए सब्सिडी नीति में बदलाव की जरूरत पड़ेगी। साथ ही सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में जो भी इस दिशा में बेहतर उत्पाद उपलब्ध कराता है उसे मौका दिया जाना चाहिए। वहीं क्रॉप न्यूट्रीशन से आर्थिक फायदे का आकलन किया जाना जरूरी है। अधिक न्यूट्रिशन अगर उत्पादकता और आर्थिक फायदे पर कारगर नहीं है तो उसे हतोत्साहित किया जाना चाहिए। लेकिन यहां नीति को पारदर्शी बनाना होगा।

इसके बाद है क्रॉप प्रोटेक्शन। पिछले कई दशकों में फसलों में कीटनाशकों का उपयोग काफी बढ़ा है। साथ ही फसलों की किस्में बीमारियों से प्रभावित होने की दर भी बढ़ी है। इसके लिए इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट को केंद्र में रखकर केमिकल और बॉयो केमिकल दोनों तरह के उत्पादों का उपयोग जरूरी है। लेकिन यह बात भी सही है कि एग्रोकेमिकल मे मॉलिक्यूल विकसित करने में हमारे देश की कंपनियों का रिकॉर्ड बहुत औसत है। अधिकांश निर्भरता विदेशों में विकसित मॉलिक्यूल और वहां से आयातिक मैटीरियल पर है। साथ ही नकली पेस्टीसाइड की एक

आज किसान का बेटा चपरासी बनना तो पसंद करता है लेकिन वह खेती नहीं करना चाहता। खेती के प्रति के आकर्षण तभी बढ़ेगा जब इसमें फायदा दिखेगा।

डॉ. चंद्रपाल सिंह
चेयरमैन, कृभको

Photo: Unsplash.com

मार्केट लिंकेज के बिना कृषि का विकास नहीं हो सकता है। इसमें सरकारी नीतियों का बड़ा योगदान है। नीतिगत समर्थन से ही एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा मिला।

रोशन लाल टामक
ईडी व सीईओ, शुगर बिजनेस, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड

पैरेलल इंडस्ट्री देश में चल रही है। जिसका खामियाजा किसानों को आर्थिक रूप से और फसल नुकसान दोनों रूप में भुगतना पड़ता है। इस मसले पर भी सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। साथ में अगर जीएम किस्मों के जरिये क्रॉप प्रोटेक्शन में कामयाबी मिलती है तो जहां संभव है वहां इसका फायदा लिया जा सकता है।

अगला और अहम फैक्टर है एग्रोनॉमिक इंटरवेंशन। इसका दायरा वृहद है। इसमें फसल की लागत के आकलन से लेकर मार्केटिंग के पक्ष को को भी जोड़ा जा सकता है। इस मोर्चे पर हमारे देश में रिसर्च और अध्ययन की कमी को नकारा नहीं जा सकता है। अगर इस पर सही तरीके से अमल होता है तो यह किसानों और कृषि के लिए फायदेमंद होगा। शोध संस्थानों के ट्रॉयल फील्ड की उत्पादन लागत के आंकड़े सामने आने चाहिए और उन किस्मों का किसानों के खेतों में उत्पादन, उत्पादकता और लागत के साथ तुलनात्मक अध्ययन की जरूरत है।

कृषि क्षेत्र के विकास और यहां निवेश की संभावनाओं पर भी बात करना जरूरी है। नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद का कहना है कि 4.5 फीसदी की कृषि विकास दर के जरिये ही 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र का सपना पूरा कर सकता है। ऐसे में सरकार के सामने एक बेहतर मौका है कि वह कृषि को केंद्र में रखकर अपनी आर्थिक नीतियां तय करे। हालांकि अभी ऐसा नहीं हो रहा है लेकिन ऐसा करना जरूरी है क्योंकि कृषि क्षेत्र में बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं जो देश के विकास की गति को तेज कर सकती हैं। लेकिन उसके लिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी नीतियों में बदलाव करना होगा और निवेश के लिए बेहत मौके पैदा करने होंगे।

चिंताजनक बात यह है कि कृषि क्षेत्र में निवेश करने में निजी कारपोरेट क्षेत्र की दिलचस्पी बहुत कम है और यह तीन फीसदी से भी कम है। कृषि क्षेत्र में अधिकांश निवेश या तो सार्वजनिक निवेश है फिर किसानों का खुद का निवेश है। यह स्थिति कृषि के विकास के पहिये को तेज नहीं कर सकती है। केंद्र और राज्य सरकारें अपने बजट में कृषि क्षेत्र के लिए आवंटित राशि का बड़ा हिस्सा इनकम सपोर्ट या सब्सिडी के रूप में दे रही हैं, वहीं कैपिटल एक्सपेंडिचर इनका खर्च नगण्य है। चालू साल के केंद्रीय बजट में कृषि के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर 100 करोड़ रुपये से भी कम है जबकि सरकार ने 11.11 लाख करोड़ रुपये के कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रावधान किया है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा ढांचागत सुविधाओं के विकास पर जा रहा है। यही नहीं एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन पर सरकार का खर्च या तो स्थिर है या कम हो रहा है।

सहकार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डीएन ठाकुर किसानों की पूंजी की समस्या को दूर करने के लिए सॉवरिन फंड बनाने की वकालत करते हैं। इस फंड के जरिए बैंकों को गारंटी दी जाए ताकि वे किसानों को आसानी से कर्ज दे सकें। उनका कहना है कि गांव के स्तर पर सहकारी संस्थाओं को इतना समर्थ बना दिया जाए कि वह अपने सदस्य - हर किसान के एक-एक दाने की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कर सकें और किसानों को उपज बेचने में परेशानी न हो। इतने बड़े देश में कोऑपरेटिव के अलग-अलग मॉडल अपनाने की जरूरत है।

यहां जिन मुद्दों को केंद्र में रखा गया है वह सब एक समग्र कृषि नीति का हिस्सा होंगे तो कृषि क्षेत्र की आर्थिक संभावनाओं का फायदा उठाया जा सकेगा। उत्पादन के बराबर ही अहमियत कृषि उत्पादों के मूल्य और मार्केटिंग ढांचे की है। इसके लिए किसान की आय को केंद्र में रखने की जरूत है। घरेलू उत्पादन, बाजार में उपलब्धता, कीमतें और आयात-निर्यात के फैसलों के केंद्र में उपभोक्ता को रखने की नीति को बदलने की जरूरत है। यहां सबसे चर्चित मुद्दे न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के मामले में यह सोच अपनानी होगी कि किसानों को यह दाम कैसे दिया जाए।

कृषि में ग्रोथ के अवसर तलाशने होंगे

प्रो. रमेश चंद

लेखक नीति आयोग के सदस्य हैं।

भारत की आजादी के समय रूस में कलेक्टिव फार्मिंग की व्यवस्था थी, चीन में कम्यून सिस्टम था। उसमें सभी किसानों की जमीन मिलाकर खेती करने की व्यवस्था थी। उसमें किसी किसान की व्यक्तिगत जमीन नहीं होती थी। हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत में भी ऐसी व्यवस्था चाहते थे। चौधरी चरण सिंह ने उस नीति के विरोध में किताब लिखी थी- जॉइंट फार्मिंग एक्सरेड। वे मानते थे कि भारत के किसानों का जमीन के साथ जुड़ाव संतान से भी ज्यादा है। आप चाहे उन्हें कलेक्टिव फार्मिंग के जितने आर्थिक लाभ बताएं, जमीन के साथ मां-बेटे का रिश्ता होने के कारण वे कभी इसके लिए तैयार नहीं होंगे, और न ही हमें इसका प्रयास करना चाहिए। उन्होंने किताब में इसके पक्ष में अच्छी दलीलें भी दी हैं। इससे कृषि के प्रति उनकी दूरदर्शिता का भी पता चलता है। यह भी कि वे कृषि, कृषक और ग्रामीण व्यवस्था को किस तरह देखते थे। इतने वर्षों के बाद भी उनकी बातें प्रासंगिक हैं। उन्होंने जो ग्रामीण कुटीर उद्योग को फोकस में रख कर ग्रामीण विकास करने की पैरवी की थी, आज हम दोबारा उसी की बात कर रहे हैं। आज हम एग्रीकल्चर-इंडस्ट्री लिंकेज पर जोर दे रहे हैं।

कृषि को इकोनॉमिक ग्रोथ का इंजन बनाने के लिए हमें कृषि के इर्द-गिर्द वातावरण के हिसाब से ही सोचना पड़ेगा। उस वातावरण से हटकर अगर हम सोचेंगे तो एक विरोधाभास पैदा होगा और बहुत ज्यादा सफलता भी नहीं मिलेगी। अगर हम समय और परिस्थिति के अनुसार अपने सेक्टर को आगे बढ़ाएं तो उसमें सफलता की संभावना अधिक होगी और गतिरोध भी नहीं होगा। हम रोज सुनते हैं कि देश का एजेंडा विकसित भारत का है। आगे विकसित भारत का लक्ष्य ही देश की प्राथमिकताओं को दिशानिर्देशित करेगा। प्रधानमंत्री ने भी नीति आयोग से इसका विजन तैयार करने के लिए कहा है कि 2047 का भारत विकसित भारत हो। देश दो चीजें लेकर चल रहा है। एक तो यह कि देश को विकसित बनाना है और दूसरा उसे विकसित सब की भागीदारी से बनाना है।

विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अगले 24 वर्षों तक हमारी अर्थव्यवस्था के आउटपुट में सात से आठ प्रतिशत ग्रोथ चाहिए। अगर हम इतने वर्षों तक इस दर से आगे बढ़ेंगे तो हमारी प्रति व्यक्ति आय इतनी हो जाएगी की हम विकसित देश कहलाने के काबिल हो जाएंगे। वर्ल्ड बैंक के अनुसार जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 12,000 डॉलर यानी 10 लाख रुपए से ऊपर होगी उसे हम विकसित कह सकते हैं। अभी प्रति व्यक्ति आय 1,70,000 हजार रुपए के आस-पास है। हमें उसे 24 साल में 6 से 7 गुना करना है। देश ने विकास के इसी रास्ते पर जाने का फैसला किया है और सभी नीतियां इसी के इर्द-गिर्द बनाई जाएंगी।

24 वर्षों तक इतनी ग्रोथ हासिल करने के लिए सभी गतिविधियों को शामिल करना पड़ेगा, चाहे वह कृषि हो, इंडस्ट्री हो या सर्विसेज हो। लेकिन मेरे विचार से कृषि क्षेत्र की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। इसके कई कारण हैं। हम इकोनॉमी को 12 भागों में बांटते हैं और उसमें सबसे बड़ा कृषि क्षेत्र ही है। मैन्युफैक्चरिंग अब उसके करीब पहुंच गया है। देश की 18 से 20 प्रतिशत आय कृषि क्षेत्र से आती है। अगर इतनी बड़ी हिस्सेदारी वाला सेगमेंट 3.5% से 4% सालाना की दर से नहीं बढ़ेगा तो विकसित भारत का लक्ष्य पाने में बहुत मुश्किल आएगी, यह असंभव भी हो सकता है। इसलिए कृषि क्षेत्र की भूमिका महत्वपूर्ण है। इसमें ऊंची विकास दर सुनिश्चित किए बिना विकसित भारत का सपना पूरा करने में सफलता नहीं मिलेगी।

इसमें निराश होने की बात भी नहीं है। जब आप कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो उस तक पहुंचाने के रास्ते तलाशते हैं। अगर कृषि क्षेत्र की ग्रोथ वांछित नहीं होती है तो देश तब भी विकसित होगा, लेकिन हम जो चाहते हैं कि देश में गरीबी न हो, कुपोषण न हो, लोग भूखे न रहें और विकास समावेशी हो, तो वह ग्रोथ नहीं मिलेगी। हो सकता है 40 प्रतिशत लोगों की आय ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन बाकी लोगों की स्थिति वही रहे जो पहले थी। वह ग्रोथ इनक्लूसिव नहीं होगी।

सवाल है कि हम कृषि क्षेत्र से जिस भूमिका की उम्मीद करते हैं, क्या वह वैसी भूमिका निभा सकता है। मैं आशावादी व्यक्ति हूं और मुझे लगता है कि ऐसी कोई वजह नहीं जिससे देश को विकसित बनाने में कृषि क्षेत्र अपनी भूमिका से पीछे रहेगा। लेकिन उसके लिए हमें अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। मैं कृषक परिवार से हूं, इसलिए कृषि क्षेत्र से मेरा भावनात्मक जुड़ाव रहता है। मेरी राय में सबसे पहले कृषि क्षेत्र के प्रति अपना नजरिया नकारात्मक से बदलकर सकारात्मक की ओर लेकर जाना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपनी आंखें मूंद लूं कि वहां कोई समस्या या चुनौती नहीं है। वहां समस्याएं हैं, लेकिन बड़े अवसर भी हैं। मैं इसके दर्जनों उदाहरण दे सकता हूं।

हमारे कुछ राज्य 20 साल से कृषि क्षेत्र में इतनी तेजी से विकास कर रहे हैं कि वहां गैर-कृषि क्षेत्र में भी उतना तेज विकास नहीं है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश इसके उदाहरण हैं। इन राज्यों में कृषि क्षेत्र की विकास दर छह प्रतिशत से ज्यादा है। वहां इंडस्ट्री की ग्रोथ भी इतनी नहीं है। वहां से एक भरोसा आता है कि अगर ये राज्य 6-7% की दर से कृषि विकास हासिल कर सकते हैं तो उनकी नीति को अपना कर हम पूरे देश में कृषि को इस ग्रोथ रेट से आगे क्यों नहीं बढ़ा सकते। यह उदाहरण किसी एक किसान, एक गांव का या एक जिले का नहीं, यह पूरे प्रदेश का उदाहरण है और वे सब बड़े प्रदेश हैं। इसी से हमें यह भरोसा मिलता है कि अगर सही नीतियां बनाई जाएं तो कृषि आर्थिक विकास का इंजन हो सकता है।

कई बार यह सवाल भी उठता है कि कृषि की हालत खराब है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मैं पूरी संवेदना के साथ एक उदाहरण देना चाहूंगा। अगर किसी गांव में 1000 युवा हैं और उनमें से 5-10% किसी वजह से कुपोषित या बीमार हैं तो क्या वह गांव खिलाड़ी तैयार करने का प्रयत्न नहीं करेगा? हम सही कदम उठाकर 80-90% लोगों की तकदीर बदल सकते हैं। लेकिन ये बातें सिर्फ कहने के लिए नहीं, इन्हें वास्तविकता का रूप भी देना होगा। मैं यहां दो-चार बातों की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि कृषि में लंबे समय तक ऊंची विकास दर रखना कैसे संभव है। कृषि क्षेत्र रोजगार का बड़ा साधन रहा है और आगे भी रहेगा।

सवाल है कि कृषि में ग्रोथ के अवसर कहां-कहां से होंगे। बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहां अब भी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। उदाहरण के लिए असम में गाय-भैंस की औसत उत्पादकता दो किलो प्रतिदिन से भी कम है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर दो किलो वाला पंजाब या हरियाणा की तरह 8 किलो के स्तर पर आना चाहे तो उसके लिए 400% वृद्धि के अवसर हैं। इसी तरह किसी और फसल की उत्पादकता देख लीजिए। कहीं तो आपको मिलेगा कि हम एक एकड़ में 18 से 20 क्विंटल गेहूं लेते हैं और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम 6 से 7 क्विंटल गेहूं ही ले पाते हैं। इसी तरह अन्य फसलों में, मवेशियों में, फिशरीज में, एग्रो फॉरेस्ट्री में संभावनाएं हैं।

एक और अवसर पैदा होना शुरू हुआ है क्वालिटी फूड में। आपने देखा होगा कि गांव में कई जगह दूध 35 से 40 रुपये लीटर बिकता है तो कहीं 200-300 रुपये लीटर भी बिकता है। आप दूध का उत्पादन करके अपनी आय दो से तीन गुना कर सकते हैं। आज इस देश में बहुत से ऐसे उपभोक्ता हैं जो क्वालिटी के लिए कीमत देने को तैयार हैं। यह सिर्फ दूध की बात नहीं है। आप चावल भी देख लें। यह 30 रुपये किलो बिकता है और 100 रुपये किलो से अधिक भी। इस तरह हम देखते हैं कि क्वालिटी को लेकर काफी संभावनाएं हैं। कृषि में नए तरह की डिमांड आ रही है। कृषि सिर्फ खाद्य का साधन नहीं रह गया है, बल्कि अब लोग इसे अपनी सेहत ठीक रखने में और बीमारी दूर करने में भी प्रयोग करने लगे हैं। साबुन, टूथपेस्ट और बहुत से इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी अब बायो किस्म के बनने लगे हैं। ग्रीन क्रेडिट में भी संभावनाएं हैं। इसके बारे में सरकार ने हाल ही घोषणा की है। सोलर एनर्जी को इस्तेमाल करने का अवसर है। यहां तक कि कृषि क्षेत्र में टूरिज्म की संभावनाएं भी आ रही हैं। बहुत से लोग शहर में रहते-रहते जीवन से इतना ऊब गए हैं कि वे गांव में जाकर रहना चाहते हैं। लेकिन इन सबके लिए हमें सकारात्मक फैलानी पड़ेगी और विकास के संसाधनों का प्रयोग करना होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का अपना महत्व है। मैंने पिछले दिनों संसदीय समिति को बताया कि कई जगह आप एमएसपी सुनिश्चित कर दीजिए तो वहां ग्रोथ दोगुनी हो जाएगी। उनमें उत्तर प्रदेश भी एक है। ऐसे बहुत से प्रदेश हैं जहां आप चाहे जितनी मर्जी एमएसपी देते रहें, ग्रोथ नहीं होगी। वहां सैचुरेशन हो चुका है, वहां कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे प्रदेश भी हैं जहां एमएसपी मिलता ही नहीं। वहां अगर आप एमएसपी दें तो ग्रोथ रेट एकदम से दोगुनी हो जाएगी।

किसानों को अगर बाजार तक पहुंच का अवसर मिले तो उससे भी ग्रोथ तेजी से होगी। इस दिशा में भी कई कदम उठाए गए हैं। बिचौलियों का नेक्सस भी तोड़ने का प्रयत्न किया गया था, लेकिन कुछ किसान भाइयों की समझ से शायद वह ठीक नहीं था। आपने ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) के बारे में सुना होगा। जैसे कोई इंडस्ट्री वाला अपना प्रोडक्ट अमेजॉन या किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर बेच सकता है वैसे ही किसान, किसान संस्था या कोई और अपना प्रोडक्ट ओएनडीसी पर ऑनलाइन बेच सकता है। आप वेबसाइट पर उसकी मात्रा, क्वालिटी, कीमत आदि की जानकारी दीजिए। जिसे उसकी जरूरत होगी वह साइट पर देखेगा तो बिना किसी बिचौलिए के वह खरीद सकता है। मैंने पिछले दिनों इसकी समीक्षा की थी। मुझे यह सबसे अधिक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी लग रही है। इसी तरह सहकारिता क्षेत्र को भी भूमिका निभानी चाहिए, जो अभी डेयरी क्षेत्र तक सीमित रहा है। जहां कोऑपरेटिव अच्छा काम नहीं कर रहे हैं वहां भी डेयरी सेक्टर में अच्छा काम हो रहा है।

(यह लेख रूरल वॉयस एग्रीकल्चर कॉन्क्लेव एंड नेकॉफ अवार्ड में दिए उनके मुख्य संबोधन पर आधारित है)

देश की 18 से 20 प्रतिशत आय कृषि क्षेत्र से आती है। अगर इतनी बड़ी हिस्सेदारी वाला सेगमेंट 3.5% से 4% सालाना की दर से नहीं बढ़ेगा तो विकसित भारत का लक्ष्य पाने में बहुत मुश्किल आएगी, यह असंभव भी हो सकता है।

नीति निर्माण के केंद्र में कृषि को लाना जरूरी

प्रवेश शर्मा

लेखक एग्रीटेक कंपनी समुन्नति एग्रो के डायरेक्टर और मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि सचिव हैं

भारतीय कृषि को चार समस्याओं ने बुरे तरीके से प्रभावित किया है। पहला आय का संकट है। कृषक परिवारों की आमदनी या तो स्थिर है या घट रही है, जिसका नतीजा खेती में परिवार का निवेश न होना है। दूसरा संकट है प्राकृतिक संसाधनों, खासकर मिट्टी और पानी का क्षरण। तीसरा मानव संसाधन का बढ़ता अभाव है। किसी भी राज्य में युवा पीढ़ी का एक आकर्षक रोजगार के विकल्प के तौर पर खेती में भरोसा नहीं रह गया है। युवा वैकल्पिक आजीविका के लिए शहरों अथवा दूसरे देशों में जाना चाहता है। इन सब के साथ नया संकट जलवायु परिवर्तन का जुड़ गया है, जो हमारी कठिन मेहनत से हासिल की गई खाद्य सुरक्षा को चुनौती दे रहा है।

एक बात ऐसी भी है जो इन चारों संकटों को जोड़ती है। वह है इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक सुसंगत और समन्वय वाली नीति का नितांत अभाव। केंद्र सरकार 2020 में जो तीन कृषि कानून लेकर आई थी, उसके पक्ष अथवा विरोध में मत हो सकते हैं, लेकिन यह सच है कि कृषक समुदाय के एक बड़े वर्ग की तरफ से इन कानूनों के विरोध के बाद कृषि के प्रति नीतिगत गंभीरता नहीं दिख रही है। किसानों के विरोध के बाद तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना पड़ा था। हालांकि कृषि से जुड़ी योजनाओं पर अमल जारी है और कुल मिलाकर फूड इकोनॉमी में सरकार की तरफ से अनेक कदम उठाते देखे जा सकते हैं, लेकिन आम जन को नहीं मालूम कि ऊपर बताई चुनौतियों से निपटने के लिए दीर्घकालिक योजना क्या है।

खाद्य सुरक्षा हासिल करने के अपने इतिहास पर ही अगर हम गौर करें तो हमें इस बात के संकेत मिलते हैं कि आगे क्या करने की जरूरत है। 1950 में भारत खाद्यान्नों की भीषण कमी वाला देश था। उस समय सिर्फ 5 करोड़ टन खाद्यान्नों का सालाना उत्पादन होता था। पिछले वर्ष का आंकड़ा देखें तो हम 33 करोड़ टन तक पहुंच गए हैं। किसी भी पैमाने पर देखें तो स्वतंत्र भारत की यह सबसे बड़ी उपलब्धियों में एक है। अंग्रेजों की एक सदी से भी ज्यादा चली शोषणकारी नीतियों के कारण कृषि क्षेत्र को काफी नुकसान पहुंचा था, लेकिन इसमें सिर्फ तीन दशक में उल्लेखनीय सुधार किया गया। केंद्र और राज्य सरकारों की तरफ से इसके लिए दूरदर्शी नीतियां अपनाई गईं। कृषि वैज्ञानिकों ने समर्पण दिखाया तो फील्ड में तैनात प्रशासकों ने भी कठिन परिश्रम किया। इन सब के ऊपर जटिल नई टेक्नोलॉजी और कृषि प्रबंधन प्रणाली को अपनाने में कृषक समुदाय की भागीदारी रही।

तथाकथित हरित क्रांति एक व्यापक इकोसिस्टम के विकास को दर्शाती है, जिसे भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने और खाद्य सुरक्षा हासिल करने के मकसद से अपनाया गया था। इस इकोसिस्टम में अनुसंधान संस्थानों, एक्सटेंशन मशीनरी, क्रेडिट और इनपुट, सप्लाई चेन, मार्केटिंग और खरीद का इंफ्रास्ट्रक्चर तथा पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली शामिल हैं, जिनकी मदद से खाद्य की भीषण कमी और अकाल जैसी परिस्थितियों को स्थायी रूप से खत्म किया जा सका। इस महत्वाकांक्षी परियोजना में बड़ा काम केंद्र सरकार की तरफ से किया गया, लेकिन इस प्रयास को राज्यों का भी पूर्ण समर्थन मिला। यहां यह बात भी उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की ऐतिहासिक उपलब्धि को लेकर नई पीढ़ी के नेताओं, नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और प्रशासकों में गर्व का अभाव तथा अज्ञानता आज के समय की बड़ी पहेली है।

हरित क्रांति के दौर की उपलब्धियों की इस संक्षिप्त समीक्षा से तीन बड़ी सीख मिलती हैं।

1. नीति के स्तर पर लक्ष्य स्पष्ट रूप से निर्धारित थे, उन लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक इकोसिस्टम तैयार किया गया तथा समग्र नजरिया अपनाया गया।
2. तीन दशक के लंबे समय तक केंद्र और राज्य सरकारों ने बेहतरीन समन्वय के साथ काम किया, सभी पक्ष उन्हें दी गई जिम्मेदारियों और भूमिका के प्रति पूरी तरह समर्पित थे।
3. नीति निर्माण का आधार नॉलेज यानी जानकारी था। केंद्र और राज्य सरकारों के संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण अनुसंधान को बड़ी अहमियत दी जाती थी। साथ ही एक मजबूत डेटा संग्रह और मॉनिटरिंग ढांचा तैयार किया जा रहा था।

क्या हरित क्रांति का समय हमें भविष्य के लिए कोई दिशा दे सकता है? मेरे विचार से हमें उस दौर से मिली सीख पर अमल करना चाहिए जिसने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने में हमारी मदद की।

इस संदर्भ में तीन विचार ध्यानार्थ रख रहा हूं-

सबसे पहली जरूरत केंद्र और राज्यों के बीच भरोसे

और समन्वय के रिश्ते को दोबारा स्थापित करने की है, ताकि कृषि में अगले चरण की नीतिगत चुनौतियों से निपटा जा सके। इसके बिना हम जो इकोसिस्टम को दुरुस्त करने और मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं, उसे हासिल कर पाना मुश्किल लगता है। चाहे केंद्र हो अथवा राज्य, शीर्ष राजनीतिक स्तर पर अभी ऐसी कोई स्थायी व्यवस्था नहीं नजर आती जहां बिना राजनीतिक पक्षपात के कृषि नीति की चुनौतियों और उनके विकल्पों पर चर्चा की जा सके। हमें कृषि के क्षेत्र में भी जीएसटी काउंसिल की तर्ज पर एक बॉडी गठित करने की जरूरत है जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री, या नहीं तो कम से कम केंद्रीय कृषि मंत्री करें। बीते दो दशकों में नीति के स्तर पर जो सुस्ती देखने को मिल रही है, उसे तोड़ने की दिशा में यह पहला कदम होगा। इसके बाद ही कृषि इकोसिस्टम के पुनर्निर्माण की महती जरूरत पर फोकस किया जा सकेगा।

दूसरी राय यह है कि अनुसंधान से लेकर एक्सटेंशन तक, फाइनेंसिंग से लेकर ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर तक और टेक्नोलॉजी से लेकर मार्केटिंग तक, कृषि इकोसिस्टम के बिखरे पुर्जों की पहचान की जाए। विभिन्न एग्री वैल्यू चेन के समेकित विचार और विश्व बाजार में भारत के वांछित स्थान से निवेश, अनुसंधान, स्केलिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण आदि का आधार बन सकता है। हरित क्रांति की शुरुआत 5 दशक से भी अधिक पहले की गई थी। तब और अब में एक बड़ा परिवर्तन निजी क्षेत्र द्वारा क्षमता निर्माण और उनका इस सेक्टर में रुचि दिखाना है। कृषि इकोसिस्टम की क्षमता को तेजी से सुधारने में इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा सकता है, खासकर मूल्य संवर्धन और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सृजन के मामले में।

तीसरा लेकिन समान रूप से महत्वपूर्ण पहलू यह है कि योजना बनाने और उन पर अमल करने में पूरी तरह से विकेंद्रीकृत नजरिया अपनाया जाए। इसमें स्थानीय स्तर पर जमीन की स्थिति, खाद्य एवं पोषण, कृषि जलवायु स्थिति और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को शामिल किया जाए। अनुसंधान, एक्सटेंशन और नीतियों को अमल में लाने की क्षमता राज्यों और उनमें भी निचले स्तर पर विकसित की जानी चाहिए। 1960 और 1970 के दशक की तुलना में आज का कृषक समुदाय काफी अधिक जानकारी रखता है और सजग है। उस समय काफी हद तक केंद्रीकृत योजना और निवेश की जरूरत थी जिसका नेतृत्व वैज्ञानिक और प्रशासक कर रहे थे। कृषक समुदाय के इनोवेशन और उनकी जानकारी को उसमें शामिल करने की गुंजाइश बहुत कम थी। लेकिन आज के दौर में योजना बनाने और उन पर अमल करने में कृषक समुदाय को बड़ी और सक्रिय भूमिका देने की जरूरत है। उन्हें सिर्फ नीतियों के अमल में नहीं, बल्कि नीतियां बनाने में भी सहयोगी बनाने की जरूरत है।

लेख की शुरुआत में मैंने कृषि क्षेत्र के जिन चार संकटों का जिक्र किया था, उनसे निपटने के लिए ये कुछ समाधान हैं। हालांकि ये अपने आप में कोई अनूठे अथवा अंतिम समाधान नहीं हैं। जरूरी यह है कि कृषि क्षेत्र की चुनौतियां को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाय। पूरे देश को एक इकाई के तौर पर समझने के बाद ही इसका समाधान निकाला सकता है। राजनीतिक संघर्ष तो लोकतंत्र की रगों में लहू के समान है। यह संघर्ष बना रह सकता है और रहना भी चाहिए। लेकिन खाद्य और पोषण सुरक्षा विवाद का विषय नहीं हो सकता है। इसलिए यह काम करने और आगे बढ़ने का समय है।

हरित क्रांति की शुरुआत 5 दशक से भी अधिक पहले की गई थी। तब और अब में एक बड़ा परिवर्तन निजी क्षेत्र द्वारा क्षमता निर्माण और उनका इस सेक्टर में रुचि दिखाना है।

सदा ऋणी रहेगा कृषक समाज

डॉ. आर एस परोदा

पद्मभूषण से सम्मानित लेखक आईसीएआर के पूर्व डीजी और डेयर के पूर्व सचिव हैं

पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में हरित क्रांति के जनक डॉ.एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की। कृषि वैज्ञानिक समुदाय ने इसका सहर्ष स्वागत किया। डॉ. स्वामीनाथन को किसानों का वैज्ञानिक कहकर संबोधित करना भी सर्वथा उचित है, क्योंकि वे आजीवन कृषक समुदाय के कल्याण के लिए काम करते रहे। वे संभवतः एकमात्र गणमान्य व्यक्ति हैं जिन्हें सभी प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कारों से नवाजा गया- पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्मविभूषण। उनके बेहतरीन नेतृत्व और अमूल्य योगदान का ही नतीजा है कि आज भारत पूरी दुनिया में गर्व से सिर उठाकर खड़ा है। यह सबसे अधिक आबादी वाला देश होने के बावजूद खाद्यान्न की घरेलू जरूरत को पूरा करने में सक्षम है।

आज हम दुनिया में एक प्रमुख खाद्य निर्यातक देश बन गए हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली को मजबूत बनाना, पुनर्गठित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पहले महानिदेशक की भूमिका निभाना, कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में कार्य करना, कृषि अनुसंधान सेवा की शुरुआत करना तथा ऐसे अनेक सुधार कार्य हैं जिन्हें डॉ.स्वामीनाथन के योगदान के रूप में याद किया जाएगा। वे दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित कृषि वैज्ञानिकों में शुमार किए जाते हैं।

डॉ. स्वामीनाथन को 1987 में पहला वर्ल्ड फूड प्राइज मिला। सामुदायिक नेतृत्व के लिए उन्हें 1971 में मैगसेसे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। उन्हें 1987 में अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड, 1994 में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, 1994 में ही यूएनईपी सासाकावा एनवायरमेंट पुरस्कार, 1999 में यूनेस्को गांधी गोल्ड मेडल तथा अन्य अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। वे इंडियन साइंस कांग्रेस के प्रेसिडेंट के साथ खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) काउंसिल के चेयरमैन भी थे। वे अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (आईआरआरआई) के महानिदेशक पद पर भी रहे और चेन्नई स्थित एमएस स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष भी थे। अपने जीवन काल में उन्होंने जो सम्मान हासिल किया वह उनके अमूल्य योगदान की गवाही देता है। ये सम्मान कृषि और ग्रामीण विकास के लिए उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाते हैं।

उनके जाने से जो स्थान रिक्त हुआ उसे भर पाना बहुत मुश्किल है। वे दूरद्रष्टा होने के साथ महान व्यक्तित्व के भी मालिक थे। और सबसे बड़ी बात किसान आयोग के अध्यक्ष के तौर पर उनकी सिफारिशों के कारण उनका पूरे देश में सम्मान किया जाता है। उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए किसान की लागत और 50% राशि (सी2 प्लस 50%) की सिफारिश की थी। किसानों और भारतीय कृषि के प्रति उनके प्रेम के कारण पूरा कृषक समुदाय उनका कृतज्ञ है।

समस्त कृषि वैज्ञानिक समुदाय इस बात से प्रसन्न है कि खाद्य एवं पोषण सुरक्षा में डॉ. स्वामीनाथन के योगदान को स्वीकार करते हुए उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान, भारत रत्न दिया गया। उनके जीवित रहते अगर यह सम्मान दिया जाता तो बेहतर होता।

डॉ. स्वामीनाथन एक महानायक, महान द्रष्टा, नीति निर्माता और बेहतरीन व्यक्ति थे। वे भारत के महान सपूत थे। अखिल भारतीय कृषि अनुसंधान सेवा (एआरएस) गठित करने में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसकी वजह से देश के हर कोने में कृषि वैज्ञानिकों को अनुसंधान में मदद मिली। देश को खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बनाने में उनका योगदान अमूल्य है। उन्होंने बौने गेहूं की वैरायटी विकसित की जिसके कारण देश में खाद्यान्न उत्पादन जो 1950 में 5 करोड़ टन था, अब 33 करोड़ टन पहुंच गया है। इसलिए भारत आयातक देश से निर्यातक देश बन सका।

वैज्ञानिक खोजों और उन्हें धरातल पर लागू करने के बीच अंतर को पाटने की उनकी प्रतिबद्धता का नतीजा लैब टू लैंड प्रोग्राम है। इस पहल के तहत कृषि टेक्नोलॉजी सीधे किसानों को हस्तांतरित की जाती है, ताकि अनुसंधान का लाभ हमारे खेतों में मेहनत करने वालों को तक पहुंचे। अपने पूरे विशिष्ट करियर में उन्होंने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कृषि क्षेत्र को अनेक योगदान दिया।

प्रो. स्वामीनाथन का प्रभाव और नेतृत्व भारत की सीमा के बाहर भी था। वर्ष 1982 से 1988 तक फिलीपींस में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक के तौर पर उन्होंने इस संस्थान को आगे बढ़ने की दिशा दी, जिसका पूरी दुनिया के चावल उत्पादक क्षेत्र को लाभ हुआ। वे पगवॉश कॉन्फ्रेंस और इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के प्रेसिडेंट भी रहे। वर्ष 1999 में वे महात्मा गांधी और रवींद्रनाथ टैगोर के साथ तीसरे भारतीय थे जिन्हें टाइम मैगजीन ने 20वीं सदी में एशिया के बीच सर्वाधिक प्रभावशाली लोगों में रखा था।

कृषक समुदाय के कल्याण के लिए उन्होंने आजीवन अथक प्रयास किया। किसान आयोग के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने सरकार को राष्ट्रीय किसान कल्याण नीति लाने पर राजी किया और किसानों को बतौर एमएसपी लागत और 50% राशि (सी2 प्लस 50%) देने की सिफारिश की। इसके लिए कृषक समुदाय में उनका काफी सम्मान किया जाता है। उम्मीद है कि एक राष्ट्रीय किसान कल्याण नीति के उनके सपने को संसद में यथाशीघ्र मंजूरी मिल जाएगी।

प्रासंगिकता के साथ उत्कृष्टता, जोश के साथ कठिन परिश्रम, समाज के लिए विज्ञान, विनम्रता के साथ गुणवत्ता, यह सब उनके पूरे जीवन काल की अमूल्य सीख हैं। मेरा मानना है कि उनकी उपलब्धियां युवा पीढ़ी को भारतीय कृषि को एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करती रहेंगी।

डॉ. स्वामीनाथन का प्रभाव और नेतृत्व भारत की सीमाओं के बाहर भी था। वर्ष 1982 से 1988 तक फिलीपींस में अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक के तौर पर उन्होंने इस संस्थान को आगे बढ़ने की दिशा दी

चौधरी चरण सिंह कैसे बने किसानों के मसीहा

अजीत सिंह

लेखक रूरल वर्ल्ड के एसोसिएट एडिटर हैं

असली भारत गांवों में बसता है और देश की खुशहाली का रास्ता खेत- खलिहानों से होकर गुजरता है। इन बातों को देश की राजनीति में स्थापित करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने का ऐलान किया है। किसान-मजदूर और वंचित वर्ग की भलाई और गांवों की तरक्की के पैरोकार चौधरी चरण सिंह ने जब भी मौका मिला, तब ऐसे काम किए जो आज भी याद किए जाते हैं। वे लोकप्रिय जननेता ही नहीं, बल्कि गांधी जी के ग्राम स्वराज से प्रेरित प्रबुद्ध विचारक भी थे।

आईये, जानते हैं ऐसे 10 बड़े काम जिनकी वजह से चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा कहलाए:

1. चौधरी चरण सिंह ने जब कांग्रेस के जरिए राजनीति में कदम रखा तो काश्तकार जमींदारों के शोषण त्रस्त थे। इसलिए अपनी राजनीति को उन्होंने किसान-कमेरा वर्ग की भलाई का माध्यम बनाया। 1937 में जब चौधरी चरण सिंह पहली बार कांग्रेस के टिकट पर संयुक्त प्रांत के विधायक चुने गये थे, तभी से जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार के प्रयासों में जुट गये। किसानों को व्यापारियों व आढ़तियों के उत्पीड़न से बचानें के लिए संयुक्त प्रांत धारासभा में उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट बिल (कृषि उत्पादन विपणन बिल) प्रस्तुत किया। हालांकि, यह बिल पारित नहीं हो पाया। लेकिन यही से कृषि उपज मंडियों को संचालित करने वाले एपीएमसी एक्ट की नींव पड़ी जो तीन दशक बाद 1964 में चौधरी चरण सिंह यूपी में कृषि मंत्री रहने के दौरान पारित हुआ।

2. किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले चौधरी चरण सिंह खेतिहर किसानों और काश्तकारों की मुश्किलों को समझते थे। सन 1939 में उन्होंने कांग्रेस विधान मंडल दल की कार्यसमिति के सामने किसान परिवारों की संतानों के लिए सरकारी नौकरियों में 50 फीसदी आरक्षण की मांग रखी थी। हालांकि, पार्टी द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया, लेकिन इससे उनकी किसान हितैषी सोच का पता चलता है।

3. उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधारों को श्रेय चौधरी चरण सिंह को जाता है। सन 1946 में मुख्यमंत्री गोविंदबल्लभ पंत ने चौधरी चरण सिंह को अपना संसदीय सचिव नियुक्त किया। उसी दौरान उन्होंने संयुक्त प्रांत जमींदारी उन्मूलन समिति की रिपोर्ट तैयार करने में अहम भूमिका निभाई। यही रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में भूमि सुधारों का आधार बनी। हालांकि कांग्रेस और राज्य की सरकार का एक वर्ग इन भूमि सुधारों का धुर विरोधी था। इसी दौरान जमींदारी उन्मूलन पर उन्होंने अपनी पहली पुस्तक "अबोलिशन ऑफ जमींदारी: टू अल्टेरनेटिव्स" लिखी। यहीं से चौधरी साहब ग्रामीण और कृषक वर्ग के पैरोकार के तौर पर स्थापित होते चले गये।

4. आजादी के बाद उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि व्यवस्था विधेयक, 1950 को तैयार करने और इसे पारित कराने में चौधरी चरण सिंह ने गांव-किसान के प्रतिनिधि की भूमिका निभाई। इस कानून के जरिए लाखों काश्तकारों को जमीन का मालिकाना हक मिलने का रास्ता साफ हुआ। जमींदारों की ताकत और पार्टी के भीतर तमाम विरोध के बावजूद चौधरी चरण सिंह इस कानून में किसान और काश्तकार हित की बातों की शामिल करवाने में सफल रहे। इससे न सिर्फ जमींदारी प्रथा का अंत हुआ बल्कि काश्तकार जमीन के मालिक बन गये।

5. यूपी में राजस्व और कृषि मंत्री रहते हुए चौधरी चरण सिंह ने कृषि एवं ग्राम उद्योगों को कई तरह की रियायतें दिलाने में मदद की। जबकि उस समय विकास का नेहरूवादी मॉडल बड़े शहरों और बड़े उद्योगों के विकास पर केंद्रित था। 1953 में राजस्व और कृषि मंत्री के रूप में उन्होंने उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम को पारित कराया। इसके बाद 1960 में उन्होंने भू-जोतों पर हदबंदी अधिनियम] 1960 बनवाया। सीलिंग से प्राप्त भूमि को अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटित करने की नीति बनाई गई। उन्होंने साढ़े तीन एकड़ भूमि वाले किसानों को लगान में छूट भी दिलवाई। उनकी किसान हितैषी नीतियों के कारण आजादी के बाद देश में खेती-किसानी को बढ़ावा मिला।

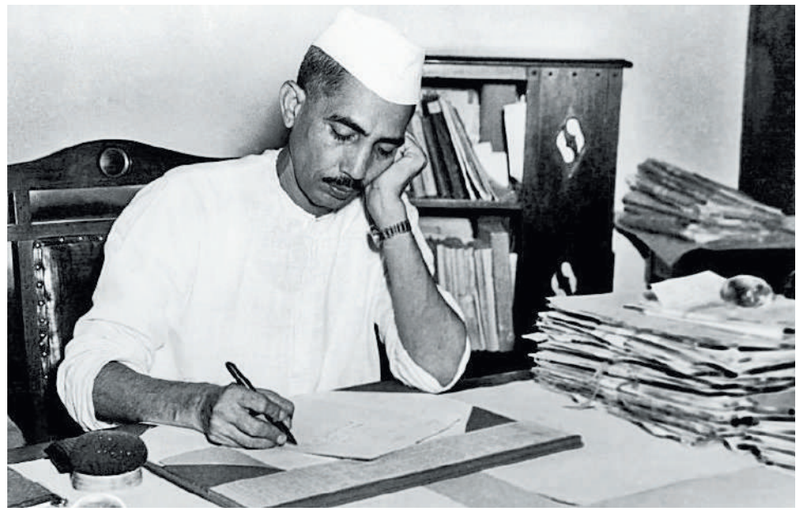

6. चौधरी चरण सिंह साफ-सुथरी छवि वाले, स्पष्टवादी, ईमानदार नेता और सख्त प्रशासक थे। 1953 में जब वे यूपी के राजस्व मंत्री थे तो प्रदेश में पटवारियों ने जमींदारों की शह पर हड़ताल कर दी। यह वो दौर था जब जमींदारी उन्मूलन कानून लागू हो रहा था। सरकार पर दबाव बनाने के लिए 27 हजार पटवारियों ने इस्तीफे दे दिए। लेकिन चौधरी चरण सिंह ने सख्त रुख अपनाते हुए अनुचित मांगों के आगे झुकने से इंकार कर दिया और सभी 27 हजार पटवारियों के इस्तीफे स्वीकार कर उनकी जगह लेखपाल का पद सृजित किया।

7. 1950 के दशक में देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू सोवियत संघ की कॉआपरेटिव फार्मिंग के मॉडल से प्रभावित होकर इसे भारत में बढ़ावा देना चाहते थे। तब चौधरी चरण सिंह कांग्रेस की ही यूपी सरकार में मंत्री थे। लेकिन किसानों के हितों को लेकर वह तत्कालीन प्रधानमंत्री और अपनी पार्टी के सर्वोच्च नेता से भी भिड़ गए थे। सन 1959 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में चौधरी चरण सिंह ने सहकारी खेती के नेहरू मॉडल का पुरजोर तरीके से विरोध किया कर अपने राजनैतिक कॅरियर को दांव पर लगा दिया। इस कदम ने चौधरी साहब को किसानों के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया। लेकिन कांग्रेस नेतृत्व से मतभेद के चलते उन्हें 19 महीने प्रदेश सरकार से बाहर रहना पड़ा। इस दौरान उन्होंने ज्वाइंट फार्मिंग एक्स-रेड: प्राब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन किताब लिखकर सहकारी खेती के विरोध को वैचारिक और तार्किक आधार दिया।

8. 1967 में कांग्रेस से अलग होने से पहले ही चौधरी चरण सिंह सरकारी नीतियों और शासन पर शहरी, पूंजीपति वर्ग के वर्चस्व के मुखर विरोधी थे। 1967 में कांग्रेस से अलग होने के बाद उन्होंने गांव-किसान विरोधी नीतियों को पुरजोर विरोध किया और देश में किसान राजनीति को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। 1977 तक चौधरी चरण सिंह खुद को किसान-कमेरा वर्ग के प्रमुख प्रवक्ता के तौर पर खुद को स्थापित कर चुके थे। कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने भारतीय क्रांति दल और फिर भारतीय लोकदल पार्टी बनाई तो उसके चुनाव चिन्ह में किसान था। आगे चलकर हलधर किसान ही जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह बना, जिसने देश में पहली गैर-कांग्रेसी सरकार बनाई।

9. चौधरी चरण सिंह किसान, मजदूर, वंचित वर्ग और ग्रामीण भारत की समस्याओं को बखूबी समझते थे। वे शहरों और बड़े उद्योगों के विकास के साथ-साथ कृषि और गांवों की तरक्की पर जोर देते थे। कृषि के अलावा गांवों के परंपरागत और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने की वकालत करते थे। उन्होंने अपने 76वें जन्म दिन पर 23 दिसंबर 1978 को दिल्ली में बोट क्लब पर ऐतिहासिक किसान रैली कर देश की राजनीति को किसानों की ताकत का अहसास कराया।

10. 1979 में उपप्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने जो केंद्रीय बजट पेश किया, जो ग्रामीण बजट के नाम से चर्चित हुआ। इसमें उन्होंने किसानों, ग्राम विकास और लघु उद्योगों पर सर्वाधिक जोर दिया। कृषि और ग्रामीण विकास के संस्थागत ऋण की समीक्षा के लिए शिवरामन कमेटी का गठन किया, जिससे आगे चलकर नाबार्ड की नींव पड़ी। प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने ही गांवों के लिए अलग से ग्रामीण पुनरुत्थान मंत्रालय बनवाया। जब भी वह सत्ता में कुछ करने की स्थिति में आए उन्होंने किसानों, भूमिहीनों, समाज के वंचित वर्ग और छोटे उद्योगों के हित में नीतिगत निर्णय लेने का प्रयास किया।

यूपी में राजस्व और कृषि मंत्री रहते हुए चौधरी चरण सिंह ने कृषि एवं ग्राम उद्योगों को कई तरह की रियायतें दिलाने में मदद की। जबकि उस समय विकास का नेहरूवादी मॉडल बड़े शहरों और बड़े उद्योगों के विकास पर केंद्रित था।

चौ. चरण सिंह का सबसे बड़ा योगदान सामूहिक खेती का विरोध

रवि शंकर कपूर

लेखक स्वतंत्र पत्रकार हैं

भारत में राजनीति में सफलता और यहां तक कि महानता इस बात से देखी जाती है कि राजनीतिक नेता किस पद पर था, वह कितने दिनों तक उस पद पर रहा इत्यादि। लेकिन यह पैमाना गलत है। उदाहरण के लिए महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने कभी कोई सरकार नहीं चलाई, लेकिन 20वीं सदी में वे किसी वायसराय अथवा प्रधानमंत्री से अधिक महत्वपूर्ण थे। इसलिए चौधरी चरण सिंह, जिन्हें नरेंद्र मोदी सरकार ने हाल ही भारत रत्न दिया, का मूल्यांकन सत्ता के ढांचे में उनके स्थान से नहीं बल्कि उनकी उपलब्धियों से किया जाना चाहिए। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कृषि के कलेक्टिवाइजेशन (सामूहिकीकरण) की बुराइयों से लड़ाई में मिली सफलता थी।

एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में कलेक्टिवाइजेशन की परिभाषा इस प्रकार है- सोवियत सरकार द्वारा अपनाई गई नीति जिसे 1929 से 1933 के दौरान काफी सघनता से लागू किया गया। इसका उद्देश्य सोवियत संघ में पारंपरिक खेती को बदलने और अमीर किसानों की आर्थिक ताकत कम करना था। इस सामूहिकीकरण के तहत किसानों को अपनी व्यक्तिगत जमीन छोड़ कर बड़े सामूहिक खेत (कोलखोजी) में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। जैसा कि ब्रिटानिका ने लिखा है, इसके नतीजे बड़े भयावह निकले, उत्पादन गिर गया। इसके बावजूद सरकार कृषि उत्पादों को बड़ी मात्रा में हासिल करती रही ताकि औद्योगिक निवेश के लिए पूंजी की जरूरत पूरी की जा सके। इसका नतीजा यह हुआ कि 1932-33 में ग्रामीण इलाकों में भीषण अकाल पड़ गया और लाखों किसानों की मौत हो गई।

चीन में भी परिणाम अलग नहीं थे। ब्रिटानिका के अनुसार, 1955 में माओवादियों ने कृषि सामूहिकीकरण की प्रक्रिया तेज कर दी। उसके बाद पूरे चीन में ग्रेट लीप फॉरवर्ड नाम से अभियान चलाया गया। इसमें पारंपरिक पंचवर्षीय योजना में बदलाव करते हुए बड़ी आबादी को लघु उद्योगों में लगाया गया। इस प्रयोग के भी बुरे परिणाम निकले। अक्षम प्रबंधन और प्राकृतिक आपदाओं के कारण 1959 से 1961 तक अकाल की स्थिति रही, जिसमें 1.5 से 3 करोड़ लोगों की जान चली गई। समाजवाद और कम्युनिज्म के परिणाम देखिए- सामूहिकीकरण से पूरी दुनिया में 20 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, कम्युनिस्ट आततायियों ने अनेक सामूहिक हत्याएं कीं। शीत युद्ध खत्म होने के बाद यह सब दुनिया के सामने आया। 1950 के दशक में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू कार्ल मार्क्स और उनके अनुयायियों के अव्यावहारिक वादों से काफी प्रभावित थे। यही कारण था कि नेहरू साझा और सहकारी खेती को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन कृषक पृष्ठभूमि वाले चरण सिंह बेहतर जानते थे। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनमें नेहरू के विचारों का विरोध करने का साहस था। उस समय ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले और नेता भी थे लेकिन उन्होंने विरोध नहीं किया। यह कुछ वैसा ही था जैसे आज भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता किसी नीतिगत मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करे। चरण सिंह उस समय कांग्रेस पार्टी के सदस्य थे। उन्होंने 1959 में नागपुर में आयोजित कांग्रेस के सालाना सत्र में अपने विचार सबके सामने रखे। उसी साल उन्होंने 'ज्वाइंट फार्मिंग एक्सरेड: द प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन' (साझा खेती पर नजर: समस्या और इसके समाधान) नाम से किताब लिखी। इसमें उन्होंने नेहरू के अव्यावहारिक विचारों के खिलाफ प्रभावशाली तर्क दिए हैं। उन्होंने लिखा है, "जमीन के साथ किसानों का जुड़ाव दुनिया के हर देश में है। जैसे, फ्रांस के किसान अपनी जमीन को 'मिस्ट्रेस' कहकर बुलाते हैं।"

उन्होंने आगे लिखा है, "मानव स्वभाव हर जगह एक सा होता है।" हमारे किसान जमीन को धरती माता कहते हैं क्योंकि यह सभी जीवों के लिए भोजन उपलब्ध कराती है। हर जगह किसान स्वतंत्रता के लिए जमीन को जरूरी समझते हैं। इसलिए सामूहिकीकरण की अर्थव्यवस्था का वह भावनात्मक तौर पर विरोध करेगा। आखिरकार यह आर्थिक क्षमता या संगठन के रूप का सवाल नहीं, बल्कि सवाल यह है कि व्यक्तिवाद या सामूहिकतावाद में से कौन बना रहेगा। खेती अर्थव्यवस्था का एक रूप मात्र नहीं बल्कि जीवन का भी एक रूप है। दुर्भाग्यवश चरण सिंह को किसानों के ऐसे नेता के रूप में जाना जाता है जो चंद हफ्तों के लिए प्रधानमंत्री बने। इसका कारण यह है कि हमारे देश में लोग उन आपदाओं के बारे में नहीं जानते जहां सामूहिकीकरण लागू किया गया। भारत में वैसी आपदा की आशंका को भांपकर उन्होंने उसे रोकने में जो भूमिका निभाई, उससे भी लोग अनभिज्ञ हैं।

चौधरी चरण सिंह सामूहिकीकरण जैसे समाजवादी चलन के लोकतंत्र पर अहितकारी प्रभाव से भी वाकिफ थे। उन्होंने लिखा है, "आजादी का पौधा सामूहिक खेत की जमीन पर नहीं उग सकता। जब हम भारत में ऐसे लोगों को देखते हैं जो लोकतंत्र का तो समर्थन करते हैं, लेकिन इसके साथ ग्रामीण समस्याओं के समाधान के लिए विशाल, साझा तौर पर चलने वाली उत्पादन इकाइयों की स्थापना की बात करते हैं, तो वैसे लोगों के साथ सहानुभूति ही रखी जा सकती है, और यह कामना की जा सकती है कि वे आराम कुर्सी पर बैठकर कोई समाधान बताने से पहले ग्रामीण भारत को ठीक से जानें।" सौभाग्यवश चौधरी चरण सिंह ग्रामीण भारत को भली भांति जानते थे।

प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में 16वें वित्त आयोग की भूमिका

टी. नंदकुमार

लेखक भारत सरकार के पूर्व खाद्य एवं कृषि सचिव हैं

16वें वित्त आयोग के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। डॉ. अरविंद पानगड़िया इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। वित्त आयोग के कार्य क्षेत्र (टर्म्स ऑफ रेफरेंस) इस प्रकार हैं:-

i. करों से जमा होने वाली कुल राशि का केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारा, जिसे संविधान के चैप्टर 1, पार्ट 12 के तहत विभाजित किया जा सकता है अथवा किया जाना है, साथ ही इस राशि में राज्यों का हिस्सा तय करना।
ii. कंसोलिडेटेड फंड ऑफ़ इंडिया में राज्यों के राजस्व में ग्रांट इन एड निर्धारित करने के सिद्धांत क्या होंगे और संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को उनके राजस्व में ग्रांट इन एड के रूप में दी जाने वाली राशि क्या होगी, यह राशि इस अनुच्छेद के क्लॉज़ 1 में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य कार्यों के लिए है।
iii. राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर वहां की पंचायतों और नगर निगमों के संसाधनों के लिए राज्य के कंसोलिडेटेड फंड में कैसे वृद्धि की जाए।

वित्त आयोग के लिए जो कार्य क्षेत्र तय किए गए हैं, वह वही हैं जो संविधान के अनुच्छेद 280 में बताए गए हैं। 15वें वित्त आयोग के कार्य क्षेत्र के विपरीत 15वें आयोग की अधिसूचना में विवाद वाले संदर्भों को दूर रखा गया है। इससे आयोग को राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को हासिल करने के लिए संसाधन आवंटित करने में आसानी हो सकती है। पूर्व के वित्त आयोगों ने गरीबी, आबादी और भौगोलिक क्षेत्र को प्रमुख बेंचमार्क के तौर पर माना था। 15वें वित्त आयोग ने वन और पारिस्थितिकी को 10% वेटेज दिया था।

13वें वित्त आयोग ने जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रयासों का विशेष उल्लेख किया था। उसने कहा था कि विभिन्न सेक्टर के बीच पानी का अविवेकपूर्ण वितरण, पानी के इस्तेमाल की कम एफिशिएंसी, जल संसाधन की प्लानिंग में खंडित नजरिया, कम यूजर चार्ज और बहुत कम रिकवरी देश में जल संसाधनों के प्रबंधन की प्रमुख समस्याओं में हैं। राज्यों के स्तर पर एक वैधानिक स्वायत्त संस्था का गठन इन मुद्दों के समाधान में मदद कर सकता है।

हमारा सुझाव है कि हर राज्य में एक जल नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाए और पानी रिकवरी का न्यूनतम शुल्क तय किया जाए। इस प्राधिकरण को निम्नलिखित कार्यों का जमा दिया जा सकता है:-

i) घरेलू, कृषि, उद्योग तथा अन्य कार्यों में इस्तेमाल होने वाले पानी का एक टैरिफ सिस्टम और शुल्क तय किया जाए और उसका नियमन किया जाए।
ii) विभिन्न श्रेणियों में और एक श्रेणी के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाले इस्तेमाल में पानी के वितरण की पात्रता तय करना और उसे रेगुलेट करना।
iii) जल क्षेत्र की लागत और राजस्व की समय-समय पर समीक्षा तथा इसकी मॉनिटरिंग करना।

आयोग ने इसके लिए 5000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे। हालांकि इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा और ना ही आगे चलकर उस दिशा में कोई प्रयास हुआ। जो भी हो, पानी उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों में सबसे प्रमुख है। प्राकृतिक संसाधनों, खासकर मिट्टी और पानी का जिस तेजी से क्षरण हो रहा है, वह गंभीर चिंता का विषय है। देश के अनेक हिस्सों में नीति निर्माता इसे लेकर चिंतित हैं तो किसान भी कृषि के भविष्य को लेकर पसोपेश में हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए राज्य के स्तर पर बड़े नीतिगत कदमों की जरूरत है। ऐसा करने में भारत की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं कभी ख्याल रखा जाना चाहिए, जिनमें प्रमुख हैं:-

- वर्ष 2027 तक एक करोड़ हेक्टेयर जमीन में प्राकृतिक खेती शुरू करना।
- वर्ष 2030 तक खराब हो चुकी 2.6 करोड़ हेक्टेयर जमीन को खेती योग्य बनाना (यूएनसीसीडी कॉप 2019)।
- वर्ष 2024 तक 41 लाख हेक्टेयर भूमि पर फसल अपशिष्ट प्रबंधन शुरू करना (आउटकम बजट 2023-24)
- भारत के 33 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वनों का विस्तार करना और पेड़-पौधे लगाना (एनएपीसीसी 2008)।
- वर्ष 2030 तक 2.5 से 3 अरब टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक का इंतजाम करना (यूएनएफसीसीसी 2015)।
- वर्ष 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करना।
- राज्यों को अतिरिक्त संसाधनों के आवंटन के बगैर इन लक्ष्यों को हासिल करना मुमकिन नहीं है।

वित्त आयोग प्राकृतिक संसाधनों के सतत संरक्षण के लिए राज्यों को संसाधन आवंटित करने में महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। वित्त आयोग पानी और मिट्टी जैसे संसाधनों का क्षरण करने वाले राज्यों को दंडित करे अथवा नहीं, यह बहस का विषय हो सकता है, लेकिन यह स्पष्ट होना चाहिए कि जो राज्य कृषि पारिस्थितिकी, पानी और मृदा संरक्षण को विभिन्न योजनाओं और सिविल सोसाइटी के प्रयासों से बढ़ावा देंगे, उन्हें पुरस्कृत किया जाएगा। इसके मानदंड और डिजाइन तैयार करने का जिम्मा आयोग पर ही होना चाहिए। कहा जा सकता है कि वित्त आयोग की गणनाओं में कृषि पारिस्थितिकी के साथ प्राकृतिक संसाधनों और वनों का संरक्षण को ज्यादा तवज्जो मिलनी चाहिए।

के.पी. सिंह
सीईओ,
हंस हैरीटेज
जैगरीज एंड फार्म
प्रोड्यूस

ग्राउंड रिपोर्ट

टेक्नोलॉजी और मार्केटिंग से गुड़-खांडसारी इंडस्ट्री का नया दौर

उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की तेजी से बढ़ी संख्या के चलते गुड़ और खांडसारी उद्योग विलुप्त होने के कगार पर आ गया था। नई सोच वाले उद्यमियों के आने और तकनीक के उपयोग से इसके दोबारा खड़ा होने की संभावना बन गई है

हरवीर सिंह

सिकंदरपुर (शामली), फुगाना (मुजफ्फरनगर)।

ऑटोमेशन, कंप्यूटर कंट्रोल, पैनल, नो ह्यूमन टच, नो पॉल्यूशन, धुंआ रहित जैसे शब्द जब गुड़ बनाने वाली इकाई के साथ जुड़ते हैं तो लोगों को सहसा यकीन नहीं होता, क्योंकि उनके जेहन में कोल्हू, क्रशर और खुले में कढ़ाह में खौलते रस से परंपरागत तरीके से गुड़ बनाने का तरीका ही होता है। लेकिन यह हकीकत है। टेक्नोलॉजी और नई मार्केटिंग की रणनीति गुड़ उद्योग के आधुनिक स्वरूप का नया रास्ता खोल रही है। जिस गुड़ उद्योग को प्रदूषण और अनहाइजनिक उत्पादन प्रक्रिया के रूप में देखा जाता है, टेक्नोलॉजी उस धारणा को बदल रही है। यही नहीं, केमिकल मुक्त और पोषकता बरकरार रखने वाले करीब चार दशक पहले बनने वाले गुणवत्ता युक्त गुड़ उत्पादों की वापसी भी हो रही है। हाइजनिक और आकर्षक पैकिंग तथा उत्पादों की बड़ी रेंज आने वाले दिनों में उपभोक्ताओं के बीच इसकी खपत बढ़ाने के साथ नये आंत्रप्रेन्योर भी पैदा कर सकती है।

चीनी उद्योग में स्थापित नाम के पी सिंह के परिवार ने शामली जिले के सिकंदरपुर गांव में हंस हैरीटेज जैगरीज एंड फार्म प्रोड्यूस के रूप में ऑटोमेटिक और नवीनतम टेक्नोलॉजी आधारित गुड़ उत्पादन संयंत्र स्थापित किया है। शुगर इंडस्ट्री में करीब 40 साल का अनुभव रखने वाले के पी सिंह देश के सबसे बड़े चीनी उद्योग समूह में शुमार बलरामपुर चीनी मिल में ग्रुप टेक्नोलॉजी हैड रहे हैं। शामली जिले के गांव ऊन के निवासी हंस हैरिटेज के सीईओ के पी सिंह रूरल वर्ल्ड के साथ हंस हैरिटेज संयंत्र के परिसर में नई तकनीक से गुड़ उत्पादन और इस उद्योग को स्थापित करने के बारे में अपने विचार साझा करते हुए कहते हैं, "मैंने चीनी उद्योग में बहुत कुछ हासिल किया। अब मेरा विचार अपने गांव में एक आधुनिक उद्योग स्थापित करने था ताकि मैं समाज को भी कुछ लौटा सकूं। इसके लिए मैने ऊन में 10 एकड़ जमीन खरीदी ताकि वहां यह संयंत्र स्थापित किया जा सके। लेकिन ऊन में राणा शुगर नाम से चीनी मिल है और सरकारी नियमों के मुताबिक चीनी मिल के 7.5 किलोमीटर के दायरे में पावर क्रशर आधारित खांडसारी इकाई स्थापित नहीं की जा सकती। इसलिए सिकंदरपुर में तीन एकड़ जमीन खरीद कर यह संयंत्र स्थापित किया। इसमें करीब 14 करोड़ रुपये का खर्च आया जिसमें कुछ मेरा पैसा था और कुछ रिश्तेदारों से लिया। बैंक से कर्ज नहीं है।"

के पी सिंह कहते हैं कि मैं नई तकनीक के जरिये गुड़ उत्पादन संयंत्र स्थापित कर एक प्रदूषण मुक्त और स्वास्थ मानदंडों पर खरा, बेहतर उत्पाद बाजार लाने के सपने को साकार करना चाहता था। इस संयंत्र में न तो पानी का कोई प्रदूषण है और न हम बगास (खोई) जलाते हैं। इसलिए धुंआ नहीं होता। पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड है, इसलिए यहां बनने वाला गुड़ हाइजनिक तो है ही, गुड़ में सुक्रोज के अलावा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद मिनरल्स भी मौजूद रहते हैं। सारा उत्पादन ग्रिड से मिलने वाली बिजली के जरिये होता है। गन्ने की क्रशिंग के लिए 20 बाई 30 इंच के चार वर्टिकल रोलर और क्रशर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके जरिये 250 टन प्रतिदिन की क्षमता हासिल की गई। इसे अतिरिक्त मिल के जरिये 100 टन प्रतिदिन तक ले जाया जा सकता है।

वह बताते हैं कि गुड़ बनाने में गन्ने के जूस की बॉयलिंग के लिए हॉट फर्नेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके लिए हीट पंप के जरिये 65 डिग्री सेल्सियस का तापमान तैयार किया जाता है। मैकेनिकल वेपर रिकंप्रेशर (वीएमआर) के जरिये 105 डिग्री की स्टीम तैयार की जाती है और 110 डिग्री पर गर्म पानी तैयार किया जाता है। हॉट वॉटर प्रेशर पंप और स्टीम की प्रकिया

के जरिये चरणबद्ध तरीके से गन्ने के रस को गुड़ में तब्दील किया जाता है। गुड़ में मौजूद मड और फॉरेन मैटेरियल को साफ करने के लिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रक्रिया में मड व फॉरेन मैटिरियल नीचे रह जाता है। वह बताते हैं कि हम इस प्रक्रिया के जरिये गन्ने से 16 फीसदी गुड़ की रिकवरी हासिल कर रहे हैं। इसमें 80 फीसदी शुगर और 20 फीसदी नॉन शुगर मैटेरियल है, जिसमें अधिकांश स्वास्थ्यवर्धक मिनरल्स शामिल हैं। उनका दावा है कि इस संयंत्र में क्रशिंग के बाद निकलने वाले बगास (खोई) में माइश्चर का स्तर 45 फीसदी होता है जो देश में किसी भी चीनी उद्योग से बेहतर है। संयंत्र को चलाने की पूरी प्रकिया कंप्यूटराइज्ड है जिसे एक्सपर्ट्स की टीम नियंत्रित करती है।

गुड़ उत्पादन की इस आधुनिकतम तकनीक का इस्तेमाल कर बेहतर गुणवत्ता और स्वास्थ्य मानकों पर खरा उतरने वाला गुड़ बन तो गया है लेकिन इसकी मार्केटिंग बहुत आसान नहीं थी। पिछले साल जनवरी में उत्पादन शुरू करने के बाद के पी सिंह गुड़ का पहला लॉट लेकर देश की मशहूर मुजफ्फरनगर गुड़ मंडी गये तो वहां आढ़ती खरीदने को तैयार नहीं थे। इसकी वजह थी गुड़ का रंग जो गहरा मटियाला है। मंडी में उस समय गुड़ की कीमत 32 रुपये किलो चल रही थी, लेकिन गुड़ के रंग की वजह से व्यापारी 26 रुपये प्रति किलो कीमत ही देने को तैयार थे। चौथे दिन मंडी में शाहनवाज नाम के व्यापारी ने गुड़ चखा तो कहा कि जो गुड़ 40 साल पहले बनता था, यह उसी तरह रवेदार और कणदार है। आपके इस गुड़ का बाजार तैयार होगा इसलिए आप व्यापारियों की बात नजरअंदाज कर यही गुड़ बनायें।

के पी सिंह बताते हैं, कुछ दिन बाद शाहनवाज संयंत्र में आये और कहा कि मैं आपका गुड़ बेचने की कोशिश करूंगा। उसने 20 दिन तक 20 ट्रक गुड़ गुजरात के अलग-अलग 20 शहरों में भेजे। हर ट्रक में 20 टन गुड़ होता था और वहां सारा गुड़ बिक गया। हालांकि गुड़ का स्टॉक जमा होने के चलते करीब आठ दिन यूनिट में शटडाउन भी करना पड़ा।

पिछले साल गुड़ की कीमत 28 रुपये से लेकर 34 रुपये तक मिली। इस साल भी करीब 90 फीसदी गुड़ उत्पादन शाहनवाज ही खरीद रहे हैं लेकिन इस साल वह इसे पंजाब में बेच रहे हैं। इस साल अभी तक 28 रुपये से 32 रुपये प्रति किलो तक की कीमत मिली है। के पी सिंह को इस साल ब्रेक इवन हासिल कर लेने का अनुमान है।

हंस हैरीटेज में जो गुड़ बन रहा है उसमें बड़ा हिस्सा गुड़ के बड़े केक पीस हैं जिनको 26 किलो की पैकिंग में बेचा जाता है। गुड़ पर 25 किलो की पैकिंग तक जीएसटी लगता है, उसके ऊपर नहीं। इसके साथ ही कंपनी छोटे पैक (जैसा ऊपर फोटो में है) में भी गुड़ बनाकर उसकी मार्केटिंग कर रही है। इसमें अच्छी पैकेजिंग में गुड़ के आधा किलो और एक किलो पैक हैं। इनका आकार चॉकलेट जैसा है। इसमें तिल और कुछ दूसरे फायदेमंद उत्पाद मिलाकर गुड़ की बेहतर मार्केटिंग की रणनीति पर भी अमल किया जा रहा है ताकि यह बड़े रिटेल चेन स्टोर की शेल्फ में जगह बना सके और हाई वैल्यू उत्पाद खरीदने वाले कस्टमर तक भी पहुंच सके।

के पी सिंह बताते हैं, हमारा गुड़ पेस्टीसाइड रेजिड्यू टेस्ट में देश में सभी मानकों पर तो खरा उतरा ही है, यह अमेरिका में 200 पेस्टीसाइड्स टेस्ट के मानकों को भी यह पूरा करता। यूरोपियन यूनियन (ईयू) में 400 पेस्टीसाइड्स टेस्ट किये जाते हैं, यह वहां के मानकों को भी पूरा करता

इस संयंत्र में न तो पानी का कोई प्रदूषण है और न हम बगास (खोई) जलाते हैं। इसलिए धुंआ नहीं होता। पूरी प्रक्रिया ऑटोमेटेड है, इसलिए यहां बनने वाला गुड़ हाइजनिक तो है ही, गुड़ में सुक्रोज के अलावा स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद मिनरल्स भी मौजूद रहते हैं।

है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि देश में च्यवनप्राश बनाने वाली कंपनियां ऐसे गुड़ को प्राथमिकता देती हैं, क्योंकि उसमें 95 फीसदी तक सूक्रोज होता है, जिसे चीनी मिलाकर तैयार किया जाता है। दवाइयों के लिए वह हमारा गुड़ खरीद रही हैं। एक दिलचस्प तथ्य यह भी है कि फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) मानकों के मुताबिक गुड़ में 90 फीसदी सूक्रोज होना चाहिए जबकि वास्तव में गुड़ में 80 से 82 फीसदी ही सूक्रोज होता है।

हंस हैरीटेज से करीब 30 किलोमीटर दूर मुजफ्फरनगर जिले के खरड़ गांव में भी एक नई गुड़ व खांडसारी इकाई फ्रेयर फूड्स लिमिटेड ने स्थापित की है। इसे स्थापित करने वाले आंत्रप्रेन्योर्स में करीब 60 साल के बिजेंद्र मलिक हैं जिनके पास एग्रीकल्चर साइंस में मास्टर्स की डिग्री है। अन्य संस्थापकों में ब्रिटेन स्थित कार्डिफ यूनिवर्सिटी से एमबीए निश्चय मलिक और फूड टेक्नोलॉजिस्ट अभिषेक मलिक हैं।

फ्रेयर फूड्स का फोकस प्रोडक्ट इन्नोवेशन पर अधिक है। प्रतिदिन 150 टन क्षमता वाला संयंत्र स्थापित करने में चार करोड़ रुपये का खर्च आया। इसमें गन्ने की क्रशिंग के लिए 3बाई2 के दो क्रशर में छह रोलर का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस यूनिट में मैकेनाइजेशन और मैनुअल तरीके से गुड़, खांडसारी और अन्य वैल्यू एडेड उत्पाद तैयार किये जा रहे हैं।

कंपनी के एक डायरेक्टर बिजेंद्र मलिक बताते हैं, हम ओपन पैन के जरिये गुड़ और खांडसारी उत्पादन कर रहे हैं लेकिन हम कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करते। गन्ने के रस को पकाने की प्रक्रिया के दौरान रस की सफाई के लिए नेचुरल हर्ब शुकलाई के एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हैं। चालू पेराई सीजन में 20 अक्तूबर, 2023 से हमने क्रशिंग शुरू की है और हम 13 फीसदी की रिकवरी ले रहे हैं।

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के नेशनल कोऑर्डिनेटर यशपाल मलिक निश्चय मलिक के पिता हैं और इस यूनिट का कांसेप्ट उन्होंने ही तैयार किया है। यशपाल मलिक ने रूरल वॉयस को संयंत्र की पूरी प्रक्रिया बताई और कहा कि यहां हम खुदरा और थोक बिक्री के लिए उत्पाद बना रहे हैं। थोक में गुड़ और खांडसारी की बिक्री किसान श्री ब्रांड के तहत की जाती है। वहीं वैल्यू एडेड उत्पादों में गुड़ चॉकलेट, गुड़ चना, चाय मसाला जैगरी पाउडर, इम्यूनिटी बूस्टर जैगरी, फ्रूट एंड नट जैगरी जैसे 9 उत्पाद बना रहे हैं और उनको आकर्षक और हाइजैनिक पैकिंग में बेच रहे हैं। हम दो किस्म का विनेगर भी बना रहे हैं। हमारा मकसद गुड़ इंडस्ट्री को हेल्थ उत्पाद इंडस्ट्री के रूप में स्थापित करना है। आयुर्वेद के साथ अब मॉडर्न हेल्थ एडवाइजर भी गुड़ के स्वास्थ्य संबंधी फायदों को लेकर बात कर रहे हैं और यह हमारे उद्योग को बढ़ावा देने का एक सकारात्मक पहलू है।

चीनी मिलों को गन्ने की कीमत के मोर्चे पर भी प्रतिस्पर्धा मिल रही है। हंस हैरिटेज को गन्ने की आपूर्ति करने आये सिकंदरपुर के किसान ईश्वर सिंह ने रूरल वॉयस को बताया कि यहां गन्ना बेचने पर उन्हें 370 रुपये प्रति क्विंटल का दाम मिल रहा है जो चीनी मिलों के राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) के बराबर है। हंस हैरिटेज मेरे गांव के पास है, इसलिए ढुलाई का खर्च व समय बचता है। भुगतान उसी दिन मेरे खाते में पहुंच जाता है। चीनी मिलों के लिए 14 दिन में

यशपाल मलिक
बिजेंद्र मलिक
अभिषेक मलिक
फ्रेयर फूड्स प्राइवेट लिमिटेड में।

यह गुड़ पेस्टीसाइड रेजिड्यू टेस्ट में देश में सभी मानकों पर तो खरा उतरा ही है, यह अमेरिका में 200 पेस्टीसाइड्स टेस्ट के मानकों को भी यह पूरा करता। यूरोपियन यूनियन में 400 पेस्टीसाइड्स टेस्ट किये जाते हैं, यह वहां के मानकों को भी पूरा करता है।

भुगतान का प्रावधान है, लेकिन यहां की ऊन और शामली चीनी मिलों में छह माह से साल भर तक की देरी से भुगतान होता रहा है। ऐसे में हंस हैरिटेज गन्ना किसानों के लिए बेहतर विकल्प के रूप में आया है। यही बात गन्ना बेचने आये किसान राजीव दोहराते हैं।

के पी सिंह कहते हैं कि पिछले साल हमने चीनी मिलों के रेट पर ही गन्ना खरीदा था और इस साल भी हम उनके बराबर रेट दे रहे हैं और पेमेंट तुरंत कर रहे हैं। फ्रेयर फूड्स के डायरेक्टर बिजेंद्र मलिक बताते हैं कि हम आपूर्ति के दिन कैश भुगतान के लिए 370 रुपये प्रति क्विंटल का रेट दे रहे हैं, जबकि 14 दिन बाद भुगतान लेने पर 385 रुपये क्विंटल का दाम दे रहे हैं। यहां गन्ना बेचने पर किसानों को सात रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त बचत होती है जो उन्हें चीनी मिल के परचेज सेंटर पर गन्ना पहुंचाने के लिए भाड़ा के रूप में देना होता है।

यशपाल मलिक कहते हैं कि हम जैगरी-खांडसारी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन बनाने पर काम कर रहे हैं। इसका मकसद गुड़ और खांडसारी उत्पादों को उपभोक्ताओं के बीच एक हेल्थ उत्पाद की तरह लोकप्रिय बनाना है। जिस तरह अंडा को एनईसीसी ने लोकप्रिय बनाया, हम भी गुड़ और खांडसारी उत्पादों को लोकप्रिय बनाकर इस उद्योग को विकसित और आधुनिक इंडस्ट्री के रूप में स्थापित करना चाहते हैं।

इन संयंत्रों को गन्ना बेचने पर किसानों को 370 रुपये क्विंटल का दाम मिल रहा है जो चीनी मिलों के एसएपी के बराबर है। ढुलाई का खर्च व समय तो बचता ही है, भुगतान भी उसी दिन किसानों के खाते में पहुंच जाता है। चीनी मिलों के लिए 14 दिन में भुगतान का प्रावधान है

नई तकनीक और मार्केटिंग रणनीति पर आधारित गुड़ और खांडसारी इकाइयों की यह शुरुआत केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, असम के लंका में स्थापित 500 टन प्रतिदिन क्षमता का एक संयंत्र भी एमवीआर तकनीक पर आधारित है। महाराष्ट्र के चालीसगांव में इस तरह का पहला संयंत्र स्थापित हुआ था जिसमें एक छोटे बॉयलर का इस्तेमाल हो रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की तेजी से बढ़ी संख्या के चलते गुड़ और खांडसारी उद्योग विलुप्त होने के कगार पर आ गया था। नई सोच वाले उद्यमियों के आने और तकनीक के उपयोग से इसके दोबारा खड़ा होने की संभावना बन गई है। तकनीक, प्रोडक्ट इन्नोवेशन व मार्केटिंग के नये प्रयोग गुड़ और खांडसारी उद्योग को नये सिरे से स्थापित करने में के पी सिंह जैसे टेक्नोलॉजिस्ट दूसरे आंत्रप्रेन्योर्स के लिए तो रास्ता खोल ही रहे हैं, गन्ना किसानों को भी चीनी मिलों के मुकाबले गन्ना आपूर्ति और बेहतर दाम का विकल्प दे रहे हैं। उपभोक्ताओं के लिए भी यह हाइजनिक और हेल्थ सप्लीमेंट का एक विकल्प है। Rw

'अन्नदाता' के लिए नया कुछ नहीं

कृषि मंत्रालय का बजट सिर्फ 740 करोड़ रुपये बढ़ा। तिलहन उत्पादन बढ़ाने की नई रणनीति बनेगी, डेयरी किसानों के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार होगा, नैनो यूरिया के बाद अब नैनो डीएपी को बढ़ावा

अजीत सिंह

आम चुनाव से पहले वित्त वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों को अन्नदाता संबोधित करते हुए कहा कि उनका कल्याण केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसानों के सशक्त तथा समृद्ध होने से देश आगे बढ़ेगा। लेकिन क्या बजट प्रावधान भी सरकार की इस भावना को दर्शाते हैं? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का बजट सिर्फ 740 करोड़ रुपये बढ़ा है। कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़े विभिन्न विभागों को देखें तो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, उर्वरक विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पशुपालन और मत्स्य पालन मंत्रालय और खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग का कुल आवंटन वित्त वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान की तुलना में लगभग तीन प्रतिशत कम हो गया है।

बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनने के लिए सरसों, मूंगफली, सोयाबीन और सूरजमुखी जैसी तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ावा देने की नई रणनीति तैयार की जाएगी। इसमें तिलहन की अधिक उत्पादकता वाली किस्मों पर शोध, आधुनिक कृषि पद्धतियों को प्रसार, मार्केट लिंकेज और वैल्यू एडिशन पर जोर दिया जाएगा। फसल कटाई के बाद की गतिविधियों जैसे स्टोरेज, सप्लाई चेन, प्रोसेसिंग और मार्केटिंग के लिए सरकारी और निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन, नेशनल लाइवस्टॉक (मवेशी) मिशन जैसी योजनाओं की सफलता से सीख लेते हुए डेयरी किसानों के लिए एक व्यापक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा। नैनो यूरिया की सफलता के बाद सरकार अब नैनो डीएपी को अपनाने पर भी जोर दे रही है। सभी कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों पर नैनो डीएपी का इस्तेमाल किया जाएगा।

कुल 47.65 लाख करोड़ रुपये के अंतरिम बजट में 2024-25 के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय को 117528.79 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि मौजूदा वित्त वर्ष का संशोधित अनुमान 116788.96 करोड़ रुपये है। तर्क यह दिया जा सकता है कि अंतरिम होने के नाते इसमें बड़ी घोषणाओं से बचा गया है। लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि पीएम किसान सम्मान निधि की घोषणा 2019-20 के अंतरिम बजट में ही की गई थी और चुनाव आचार संहिता लागू होने से पहले किसानों को इसकी दो किस्तों का भुगतान भी कर दिया गया था। इस योजना के लिए आवंटित 60,000 करोड़ रुपये की राशि में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस योजना के तहत किसानों को साल में 6,000 रुपये दिए जा रहे हैं, जिसमें वृद्धि का अनुमान था।

ग्रामीण क्षेत्र में लोगों की आय के एक प्रमुख माध्यम, मनरेगा में मौजूदा वित्त वर्ष के 60,000 करोड़ के बजट प्रावधान को संशोधित कर 86,000 करोड़ किया गया है। नए वित्त वर्ष के लिए भी 86,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है। फसल बीमा योजना की राशि में कटौती की गई है। इसे 15,000 करोड़ के संशोधित अनुमान से घटाकर 14,600 करोड़ किया गया है।

किसानों की आय बढ़ाने के लिए तमाम विशेषज्ञों के साथ सरकार भी कृषि में इनोवेशन की बात कहती है, लेकिन कृषि अनुंसधान के लिए आवंटन को मौजूदा वर्ष के 9876.60 करोड़ के संशोधित अनुमान से सिर्फ 65 करोड़ बढ़ाकर 9941.09 करोड़ रुपये किया गया है। पीएम कृषि सिंचाई योजना की राशि में जरूर उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसके लिए 8,781 करोड़ के प्रावधान को बढ़ाकर 11,391 करोड़ रुपये किया गया है।

बाजार में कीमतों में उतार-चढ़ाव से किसानों को बचाने के लिए सरकार ने प्राइस सपोर्ट स्कीम शुरू की थी। वर्ष 2022-23 में इस योजना के लिए 4007 हजार करोड़ रुपये का बजट मिला था। यह चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान में घटकर 40 करोड़ रुपये रह गया और अगले वित्त वर्ष में इसके लिए कोई प्रावधान ही नहीं किया गया है। राज्यों में दालों के वितरण के लिए सरकार ने पिछले बजट में 800 करोड़ रुपये (संशोधित 446 करोड़) का प्रावधान किया था। लेकिन इस बार इस योजना को भी बजट नहीं मिला है। पीएम अन्नदाता आय संरक्षण योजना (पीएम-आशा) के लिए 2200 करोड़ के संशोधित अनुमान को अगले वित्त वर्ष में घटाकर 1737 करोड़ कर दिया गया है।

किसान संपदा योजना के लिए इस बार 729 करोड़ का बजट रखा गया है जो पिछली बार 923 करोड़ रुपये था। देश में 10 हजार एफपीओ गठित करने की योजना के लिए पिछले बजट में 955 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जो संशोधित होकर सिर्फ 450 करोड़ रह गया। अगले वित्त वर्ष के बजट में इसे 582 करोड़ रुपये किया गया है। प्राकृतिक खेती के शोर के बावजूद इसके लिए मौजूदा वित्त वर्ष में आवंटित 459 करोड़ के बजट में से सिर्फ 100 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। अगले बजट में इसके लिए 365.64 करोड़ रुपये रखे गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सरकार लगभग एक करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनने में मदद कर चुकी है। इस सफलता से प्रेरणा लेते हुए लखपति दीदी का लक्ष्य दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ किया गया है। ड्रोन दीदी योजना के लिए बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

वित्त मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम आवास योजना के तहत केंद्र सरकार तीन करोड़ मकान बनाने के लक्ष्य को हासिल करने के करीब है। आवास की जरूरतों को देखते हुए अगले पांच वर्षों में और दो करोड़ मकान बनाए जाएंगे। सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय का बजट पिछले साल के 1.57 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2024-25 के लिए 1.77 लाख करोड़ रुपये किया है, जो लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि है। हालांकि, 1.71 लाख करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान की तुलना में यह तीन प्रतिशत ही अधिक है।

कृषि उन्नति योजना के लिए अंतरिम बजट में 7,447 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मौजूदा वित्त वर्ष का संशोधित अनुमान 6,378 करोड़ है जबकि बजट अनुमान 7,066 करोड़ था। इस योजना में खाद्य तेल-ऑयल पाम और तिलहन, बागवानी का एकीकृत विकास, कृषि विपणन जैसे मद आते हैं। मिट्टी और जल संरक्षण के लिए 38.72 करोड़ के संशोधित प्रावधान को नए साल में घटाकर 35.75 करोड़ किया गया है।

वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि पीएम-किसान सम्मान योजना के तहत 11.8 करोड़ किसानों को हर साल सीधे वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। चार करोड़ किसानों का फसल बीमा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार (eNAM) का लाभ 1361 मंडियों और 1.8 करोड़ किसानों को मिल रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना से 38 लाख किसान लाभान्वित हुए और 10 लाख रोजगार पैदा हुए हैं।

सब्सिडी की राशि में कटौती

उर्वरक सब्सिडी के लिए अंतरिम बजट सरकार ने 1.64 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह मौजूदा वित्त वर्ष के बजट में 1.75 लाख करोड़ रुपये और संशोधित अनुमान में 1.89 लाख करोड़ है। इसमें यूरिया सब्सिडी 1.19 लाख करोड़ रुपये है जो मौजूदा वित्त वर्ष के संशोधित अनुमान में 1,28,593 करोड़ है। न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी मौजूदा वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों में 60,300 करोड़ है जबकि आगामी वित्त वर्ष के लिए इसे 45,000 करोड़ रुपये रखा गया है। फूड सब्सिडी के लिए 2024-25 के बजट में 2,05,250 करोड़ रुपये रखे गए हैं। यह चालू वित्त वर्ष के संशोधित अनुमानों में 2,12,332 करोड़ रुपये है। इसके लिए इस वर्ष का बजट प्रावधान 1,97,350 करोड़ रुपये था।

कृषि संबंधी विभिन्न योजनाओं के लिए आवंटन

योजना	2023-24 (संशोधित)	2024-25 (बजट अनुमान)	अंतर
पीएम फसल बीमा	15,000	14,600	(-)3%
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना	6,150	7,553	23%
पीएम किसान सम्मान निधि	60,000	60,000	0%
एफपीओ गठन	450	582	29%
मनरेगा	86,000	86,000	0%
पीएम ग्राम सड़क योजना	17,000	12,000	(-)29%
पीएम आवास योजना	32,000	54,500	70%
फूड सब्सिडी	2,12,332	2,05,250	(-)3%
नीली क्रांति	1,500	2,352	57%
पशुधन रोग नियंत्रण	1,500	2,465	64%

(राशि करोड़ रुपये में, स्रोतः बजट दस्तावेज)

राजस्थान में बढ़ी पीएम-किसान की धनराशि

राजस्थान सरकार की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने वर्ष 2024-25 का अंतरिम पेश करते हुए जवान, किसान और महिला उत्थान पर विशेष ध्यान देने की बात कही। पीएम-किसान सम्मान निधि योजना की राशि को सालाना 6,000 रुपये से दो हजार बढ़ाकर 8000 रुपये कर दिया है। राज्य सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2,275 रुपये प्रति क्विंटल पर 125 रुपये बोनस देने का ऐलान किया है।

राजस्थान की भजनलाल सरकार ने अपना पहला लेखानुदान पेश करते हुए कृषि क्षेत्र के लिए 2000 करोड़ रुपये का राजस्थान एग्रीकल्चर इन्फ्रा मिशन का ऐलान किया है। इसके अंतर्गत 20 हजार फ्रॉम पोंड्स, 10 हजार किमी सिंचाई पाइपलाइन, 50 हजार किसानों के लिए तारबंदी जैसे कार्य कराए जाएंगे तथा ड्रोन जैसी नई तकनीक भी उपलब्ध कराई जाएगी।

सरकार निम्न आय वर्ग, छोटे किसानों, बटाईदार किसानों और खेत-मजदूरों के परिवार के छात्र-छात्राओं को "केजी से पीजी" (किंडरगार्टन से पोस्ट ग्रेजुएशन) तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी। चीनी और गुड़ पर मंडी टैक्स भी समाप्त किया गया है। किसान क्रेडिट कार्ड की तर्ज पर गोपाल क्रेडिट योजना शुरू की है। पहले चरण में 5 लाख गोपालक परिवारों को एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध कराया जाएगा। प्रदेश में मिलेट्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार 12 लाख किसानों को मक्का, 8 लाख को बाजरा, 7 लाख किसानों को सरसों और 4 लाख को मूंग के बीज उपलब्ध कराएगी।

हिमाचल सरकार ने दूध का एमएसपी बढ़ाया

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने वित्त वर्ष 2024-24 का बजट पेश करते हुए कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास पर जोर दिया। उन्होंने दूध के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) में 8 रुपये की बढ़ोतरी का ऐलान किया। साथ ही मनरेगा की दैनिक मजदूरी भी बढ़ाई। दूध का एमएसपी तय करने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने गाय के दूध का एमएसपी 38 रुपये से बढ़ाकर 45 रुपये प्रति लीटर और भैंस के दूध का एमएसपी 47 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा की। सभी दुग्ध सहकारी समितियों की देनदारियां माफ कर दी जाएंगी और दूध खरीद व प्रसंस्करण के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर 150 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि किसानों और पशुपालकों को समृद्ध बनाना हमारी प्राथमिकता है। गोवंश के लिए 1200 रुपये प्रति गोवंश अनुदान दिया जाएगा। भेड़ बकरी पालक प्रोत्साहन योजना के तहत 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। मनरेगा मजदूरों की दैनिक मजदूरी 60 रुपये बढ़ाकर 240 से 300 रुपये प्रतिदिन करने की घोषणा की।

उत्तर प्रदेश में कृषि की तीन नई योजनाएं

उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य सरकार का बजट पेश करते हुए कृषि क्षेत्र के लिए 5.1 प्रतिशत विकास दर का लक्ष्य रखा। बजट में कृषि से जुड़ी तीन नई योजनाएं शुरू की गई हैं। इसके लिए 460 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसानों के निजी नलकूपों को रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 2400 करोड़ रुपये के खर्च का प्रावधान है। वित्त मंत्री ने कहा कि डार्क जोन में नए निजी नलकूप कनेक्शन देने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया गया है जिससे लगभग एक लाख किसानों को फायदा हुआ। डार्क जोन के असफल 569 नलकूपों के लिये 70 करोड़ रुपये का बजट है। कृषि की तीन नई योजनाओं में राज्य कृषि विकास योजना, विश्व बैंक समर्थित यूपी एग्रीस योजना और ब्लॉकों व पंचायतों में ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन – ऑटोमैटिक रेन गेज लगाने की योजना शामिल है। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना के लिए 50 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत वर्ष 2024-2025 में 200 उत्पादक समूहों का गठन कर तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा।

कर्नाटक में बनेगा कृषि विकास प्राधिकरण

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बजट में जिला सहकारी सेंट्रल (डीसीसी) तथा प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास (पीआईसीएआरडी) बैंकों के मध्यम और दीर्घकालिक ओवरड्यू लोन पर ब्याज माफी का ऐलान किया है। इससे 57 हजार किसानों को राहत मिलेगी। सरकार इस योजना के तहत बैंकों को 450 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए कर्नाटक रैयत समृद्धि योजना शुरू की जाएगी। कृषि से जुड़ी नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कृषि विकास प्राधिकरण का गठन होगा। कई जिलों में किसान मॉल खोलने जाएंगे। कृषि और बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी के तहत हवाई अड्डों के नजदीक फूड पार्क स्थापित किए जाएंगे। फूलों की बिक्री और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पीपीपी के तहत बेंगलुरु में अंतरराष्ट्रीय फ्लोरीकल्चर मार्केट विकसित किया जाएगा। मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए चिक्कमगलुरु जिले में एक स्पाइस पार्क बनेगा। एक नया कार्यक्रम नम्मा मिलेट शुरू करने की योजना है।

National Federation of Cooperative Sugar Factories Ltd.

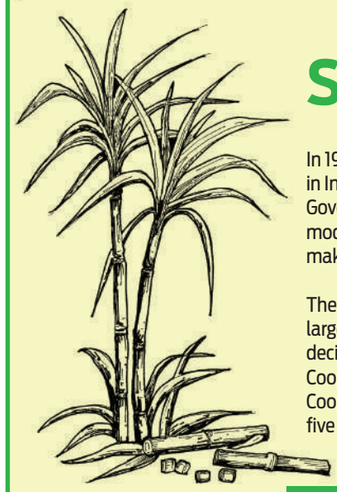

Sahakar Se Samriddhi

In 1960, NFCSF sowed the seed of revolutionising the cooperative sugar sector in India. Today NFCSF works collaboratively with the Ministry of Cooperation, Government of India to strengthen the cooperative-based economic development model, thereby accelerating the welfare of villages and farmers of the country and making cooperative sugar sector self-reliant.

The National Federation of Cooperative Sugar Factories Limited (NFCSF) is the largest Co-operative Apex sugar body in the world. The Federation has played a decisive role in establishing a nationwide network, building a strong and vibrant Cooperative sugar sector across India. 259 Cooperative Sugar Factories and 09 State Cooperative Sugar Federations across the country are its members. It represents over five crore farmers and their dependents who are involved in sugarcane cultivation.

Techno-Commercial Services Offered By NFCSF

- Sugar Cane Development
- Sugar Cane Engineering & Processing
- Distillery / Ethanol Plants
- Co-generation & Green Hydrogen
- Commercial Operations
- Financial Management & Legal Services
- Detailed Project Reports (DPR)
- Preparation of Tender Documents
- Project Management Consultancy (PMC) Services

Prakash Naiknavare
Managing Director

Ketanbhai Patel
Vice-President

Jaiprakash Dandegaonkar
President

& Board of Directors

National Federation of Cooperative Sugar Factories Ltd.
New Delhi; www.coopsugar.org

IPL
The Hallmark of Sustainability and Agro Prosperity

We Are Happy In Your Happiness

- National leader in fertilizer distribution with pan India dealer network.
- The single point-of-access for all agro nutrients in the country.
- IPL believes in empowering farmers by providing integrated solutions and educating them about sustainable farming practices.
- IPL has the philosophy of selfless service deeply entrenched in all its endeavours.
- Diversified into sugar production to support sugarcane farmers.
- Producers of vehicle grade Green Fuel (CBG) and nutrient rich Fermented Organic Manure.

Indian Potash Limited
Potash Bhawan,10-B, Rajendra Park, Pusa Road, New Delhi – 110 060
Phone: 011-25761540, 25763570, 25732436, 25725084
Fax: 011-25755313, E-mail: ipldel@potindia.com
Website: www.indianpotash.org

IPL Fertilizers - The First Choice of Wise Farmers